●वर्ष-5
●अंक-269
रायपुर, शनिवार 27 जून 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> हाउसिंग बोर्ड अब नए नाम...

राम मंदिर चंदा चोरी का मामला

एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार करें: इंद्रेश

नईदिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी की जांच बिना किसी दखल के आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले में अंतिम फ़ैसला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (स्ढ्ढञ्ज) की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाना चाहिए। लेह, लद्दाख में,ह्ढ्ढ से बात करते हुए कुमार ने कहा कि सरकार ने स्ढ्ढञ्ज का गठन कर दिया है और जांच चल रही है। हमें जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए।

उन्होंने जांच पूरी होने तक धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि मैंने मीडिया और राजनीति को भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर काफी शोर-शराबे के साथ ट्रायल करते देखा है। इसलिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब स्ढ्ढञ्ज की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, तो भारत सरकार उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी और सभी उसका स्वागत करेंगे। इस बीच, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कहा कि कथित गबन के मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान के कथित गबन के सिलसिले में 25 जून को एक स्नद्बक्र दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) शामिल हैं।

सनातन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान में कथित हेराफेरी के मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सनातन मूल्यों और लोगों की आस्था का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि अयोध्या से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, दो महीने में 70 बार हुई चोरी

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच के दौरान, जांच अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए पाया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच चोरी की 70 कोशिशें की गईं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में मनीष कुमार यादव नाम के एक व्यक्ति को कई बार चोरी की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक, मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने यह भी पाया कि दान की गिनती के दौरान उसे संभालने में बड़ी खामियां थीं। टीम ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच की, जिसमें कई प्रक्रियात्मक कमियां सामने आईं। अब तक आठ आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें चंपत राय के करीबी सहयोगी रमाशंकर यादव उर्फ़ टिन्नू यादव भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लव कुश मिश्रा, रमा शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि एसआईटी की सिफारिश के आधार पर और लोगों की गिरफ़्तारी हो सकती है। इस मामले में सख्त कार्रवाई का वादा करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

यूसीसी बिल लाने की तैयारी, विस में पेश होगा मसौदा!

भाजपा सरकार का बड़ा कदम

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पार्टी के संकल्प पत्र के मुख्य वादों में से एक था। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि विधानसभा में ष्टष्ट बिल पेश करना पश्चिम बंगाल सरकार के प्राथमिकता वाले विधायी कदमों में से एक होगा।

यह बिल अगले हफ़्ते ही पेश किया जा सकता है। इस कदम से पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के ढांचे की दिशा में कोशिशें शुरू की हैं। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया। बीजेपी नेताओं ने गुजरात और असम में भी ऐसी ही कोशिशों और चर्चाओं की ओर इशारा किया है। पार्टी नेताओं का मानना ??है कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर के कुछ हिस्सों जैसे ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले ज़िलों में इस मुद्दे के अहम राजनीतिक और सामाजिक असर हो सकते हैं।

यह बिल अगले हफ़्ते ही पेश किया जा सकता है।पश्चिम बंगाल में इस कदम से उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के ढांचे की दिशा में कोशिशें शुरू की हैं। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया। बीजेपी नेताओं ने गुजरात और असम में भी ऐसी ही कोशिशों और चर्चाओं की ओर इशारा किया है। पार्टी नेताओं का मानना ??है कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर के कुछ हिस्सों जैसे ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाले ज़िलों में इस मुद्दे के अहम राजनीतिक और सामाजिक असर हो सकते हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का एक वर्ग यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड% (समान नागरिक संहिता) की संभावना का स्वागत कर रहा है। वे इसे एक ऐसे उपाय के तौर पर देख रहे हैं जो शादी, तलाक़ और विरासत से जुड़े क़ानूनी अधिकारों को मज़बूत कर सकता है। हालाँकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है?

यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मकसद शादी, तलाक़, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग, सभी के लिए एक जैसे सिविल कानून बनाना है। इसके समर्थकों का तर्क है कि एक जैसा कानूनी ढांचा कानून के सामने समानता को बढ़ावा देता है और धर्म-आधारित पर्सनल कानूनों से पैदा होने वाले भेदभाव को खत्म करता है।

रायपुर। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को सुकमा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न विभागीय संस्थानों का निरीक्षण कर जमीनी स्तर पर संचालित योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

भारत में ईरान बहा देगा तेल की नदियां: खामेनेई

नईदिल्ली। भारत में एक बार फिर ईरानी तेल की वापसी होने जा रही है क्या? ईरान के तेल मंत्री एनर्जी मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ईरान के तेल मंत्री एनर्जी मिनिस्टर मोहसीन पाक निजाद ने साफ संकेत दिए हैं कि ईरान भारत के साथ तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। ईरान इस समय ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बहाने भारत आया है। लेकिन

असली खेल पर्दे के पीछे की द्विपक्षीय वार्ताओं में चल रहा है। इस संभावित नई डील की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में जाना होगा जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध सेंशंस नहीं लगे हुए थे। साल 2018-19 से पहले ईरान भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत किस बेहतरीन और जादुई व्यवस्था के चलते ईरान से तेल खरीदता था।

डॉलर की छुट्टी हो चुकी थी और रुपए में पेमेंट हो चुकी। भारत ईरान से जो भी तेल खरीदता था, उसका 45त्न भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि सीधे भारतीय करेंसी यानी रुपए में हुआ करती थी। इसके लिए भारत के एक बैंक में बाकायदा ईरान का एक विशेष अकाउंट खाता भी खोला गया था। बदले में भारतीय सामान भी दिया जाता था। कच्चे तेल के बदले यानी एक तरह से वाटर सिस्टम इसको कह लीजिए। ईरान उस रुपए का इस्तेमाल भारत से बासमती चावल, गेहूं, चीनी, चाय दवाइयां खरीदने के लिए करता था। यानी भारत का पैसा घूम कर भारत के किसानों और व्यापारियों के पास ही वापस आ जाता था। यानी कि भारत की इकॉनमी में ये पैसा वापस आ जाता था। तीसरा पॉइंट फ्री शिपिंग और इंश्योरेंस। ईरान भारत को तेल बेचने के लिए इस कदर बेताब रहता था उस वक्त कि वो भारतीय रिफाइनरीज को मुफ्त में फ्री में समुद्री जहाज और मुफ्त बीमा की सुविधा भी दिया करता था।

प्रमुख समाचार

सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर आज जाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वह सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत रक्षा व कूटनीतिक संबंधों के तहत इस समारोह में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और नौसेना के दो युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी होगी। पीएम मोदी सेशेल्स की संसद को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात और संवाद करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले साल 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी। मौजूदा यात्रा पूरे 11 साल बाद दोबारा होने जा रही है।

हम गद्दार नहीं, ममता बनर्जी के प्रति वफादार : कुणाल घोष

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच, पार्टी विधायक कुणाल घोष ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उत्तरी कोलकाता में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ममता बनर्जी के समर्थन तथा पार्टी नेतृत्व के पक्ष में नारे लगाए गए। कोलकाता में घोष ने कहा कि कल नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। भारी बारिश के बावजूद हॉल खचाखच भरा था और बाहर भी कार्यकर्ता जमा हुए थे। नारा था, हम गद्दार नहीं हैं, हम दीदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद टेलीफोन मैसेज के ज़रिए कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को परेशान करने के लिए झूठे केस का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही कहा कि जो लोग पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ते हैं, वे पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं।

रामलला के दरबार पहुंचे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल

लखनऊ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे उन्होंने रामलला के दरबार में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। दर्शन से पहले केजरीवाल ने कहा कि वह भगवान राम से देशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। उन्होंने बताया कि रामलला के दर्शन के बाद वह हनुमानगढ़ी जाकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके उपरांत संत-महात्माओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। अयोध्या दौरे के दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि शाम करीब चार बजे वह पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे।

रामभक्तों की अग्निपरीक्षा न लें सबूत है तो एसआईटी को दें

देवरिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीएम योगी ने यह बातें देवरिया में 456 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में कहीं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, एक पक्ष कहता था कि राम हैं ही नहीं यानी अयोध्या को भी ये लोग नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ी करते रहे और दूसरा पक्ष वो है जो जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाते थे। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे तुम हमें आस्था बताओगे? राम नवमी पर दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को प्रतिबंधित करते थे।

राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे से खरीदे जा रहे सांसद : संजय राउत

मुंबई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के मामले पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि राम मंदिर चढ़ावा के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इसका इस्तेमाल सांसदों को खरीदने में किया जा रहा है। शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शुक्रवार को अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कहा, मुख्य आरोपी अभी भी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। जो लोग खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं, वे मंदिर से करोड़ों रुपये चुराते हैं और यह पैसा राजनीति में आता है, जहां इसका इस्तेमाल सांसदों को खरीदने और राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। आपने राम मंदिर से चुराए गए 2000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों को तोड़ने के लिए किया। शिवसेना (यूबीटी) संजय राउत ने ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने पर निशाना साधा है।

पासपोर्ट, एसआईआर, नागरिकता, मतदाता और चुनाव आयोग?

सनत जैन

25 जून से पंजाब सहित कई राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो गया है। 24 जून को विदेश मंत्रालय द्वारा यह कहा गया, पासपोर्ट नागरिकता का वेध दस्तावेज नहीं है। पंजाब के नागरिकों के पास सबसे ज्यादा पासपोर्ट हैं। पंजाब के नागरिक बड़ी संख्या में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य देशों में एनआरआई के रूप में रह रहे हैं। पंजाब में हर घर में पासपोर्ट एक प्रमाणित दस्तावेज है। एसआईआर के ठीक पहले विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद पंजाब और अन्य राज्यों में नागरिकता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब लोग सरकार से पूछ रहे हैं, ऐसा कोई दस्तावेज बताएं, जो नागरिकता का प्रमाण हो। इस विवाद के शुरू होते ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की जा रही है, उसमें पासपोर्ट को भी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चुनाव आयोग इसके साथ और कौन-कौन से दस्तावेज मांगता है। यह या तो चुनाव आयोग जानता है, या भगवान जानते हैं। जैसा पश्चिम बंगाल की एसआईआर के समय चुनाव आयोग द्वारा बिहार एवं अन्य राज्यों की तुलना में अन्य नियम लागू किये। लगभग 1 करोड़ मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया। चुनाव आयोग जो कहता है, वह करता नहीं है, पश्चिम बंगाल में यही हुआ। यह लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी गई। कहीं से कोई न्याय मतदाताओं को नहीं मिला। उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिन 27 लाख मतदाताओं ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, मतदान के पहले यदि उसका निराकरण नहीं होता है, तो अगली बार मतदान कर लेना। ऐसे लाखों मतदाताओं का मतदान का संवैधानिक अधिकार छिन गया।

अभी तक एसआईआर के माध्यम से लगभग 6.50 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग हो चुके हैं। अब जिन राज्यों में चुनाव होना है। चुनाव के ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करना एक बार फिर विवादों में है। पंजाब में अभी तक भाजपा की सरकार नहीं बनी है। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार कभी नहीं बनी थी। अब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। अब भाजपा ने पंजाब को अपने निशाने पर लिया है? इस तरह के आरोप सामने आने लगे हैं। 2017 के बाद से चुनाव

आयोग में बहुत पानी बह गया है। दर्जनो सॉफ्टवेयरौं का उपयोग, चुनाव के लिए आयोग द्वारा शुरू किया गया है। उसके बारे में राजनीतिक दलों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। हर बार नए-नए सॉफ्टवेयर का उपयोग चुनाव आयोग करता है। चुनाव की निष्पक्षता को लेकर पिछले 5 वर्षों से तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। मतदान से ज्यादा वोटो की गिनती हो जाती है। ईवीएम मशीन, बीवीपेट और कंट्रोल पैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाओं के माध्यम से जो मामले चल रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, उससे राजनीतिक दलों और मतदाताओं का विश्वास चुनाव आयोग पर कम होता चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम मशीनों के जलने का समाचार आया। 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल वहां चुनाव आयोग ने तैनात कर रखा है। वीडियो फुटेज 45 दिन की समय सीमा के अंदर मांगने के बाद भी नहीं दिए जाते हैं। मतदाता सूची और फार्म 17 की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव के पहले एसआईआर शुरू करता है। चुनाव के कुछ दिन पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं। मतदाताओं को इसकी जानकारी तब मिलती है, जब वह कुछ कर नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मतदाताओं और राजनीतिक दलों में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास बढ़ता जा रहा है।

नागरिकता को लेकर भारत सरकार और चुनाव आयोग यह नहीं बता पा रहा है, कौन सा वह दस्तावेज नागरिकता के लिए मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह नहीं बताया कि भारत में नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य है। चुनाव आयोग और सरकार मिलकर जो निर्णय लेते हैं। न्याय पालिका, चुनाव आयोग को स्वतंत्र निकाय मानकर उस पर ठप्पा लगा देता है। जिसके कारण यह विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। नागरिकता मौलिक अधिकारों में शामिल है। 18 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। मतदाता सूची में कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो, कोई व्यक्ति जो पात्र है, वह मतदान करने से वंचित न हो। 1952 से लेकर 2024 तक चुनाव आयोग के बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण करते थे। मतदाता सूची तैयार करते थे। नागरिकता प्रमाणित करने का चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। फिर भी नागरिकता के नाम पर चुनाव आयोग द्वारा जो खेल खेला जा रहा है उसका सभी जगह विरोध होना शुरू हो गया है।

बड़े नक्सल डंप की रिकवरी, टेकला जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद,तोयामेटा जंगल में मिले 24 लाख नकद

नारायणपुर में सुरक्षाबलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है.सुरक्षाबलों ने कैश समेत नक्सल डंप की रिकवरी की है.

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चलाए जा रहे लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान थाना ओरछा क्षेत्र के टेकला जंगल-पहाड़ी से नक्सली डंप बरामद हुआ है। वहीं थाना छोटेडोंगर क्षेत्र के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी से 24 लाख रुपए की नकद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई नक्सलियों की सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों पर करारा प्रहार है।

नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों के संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इन्हीं अभियानों के दौरान प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।

पहली कार्रवाई थाना ओरछा क्षेत्र के टेकला जंगल-पहाड़ी में की गई। यहां जंगल के भीतर नक्सलियों के भूमिगत तरीके से छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण और विस्फोटक सामग्री के बड़े डंप का पता चला।सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सावधानीपूर्वक तलाशी ली और डंप को सुरक्षित तरीके से रिकवर कर लिया।इसी अभियान के दूसरे चरण में थाना छोटेडोंगर क्षेत्र के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई 24 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की। पुलिस के अनुसार यह नकदी नक्सली संगठन के आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जिसका उपयोग हथियार खरीदने, संगठन संचालन और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना था।

कौन से हथियार हुए बरामद ?

बरामद हथियारों में एक इंसास रायफल, दो एसएलआर रायफल, दो 1303 रायफल, दो 30-ओसी बंदूक, एक बीजीएल लॉन्चर , एक सिंगल शॉट बंदूक शामिल हैं। इसके अलावा इंसास, एसएलआर और 1303 रायफलों की मैगजीन, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, 30-ओसी के राउंड, 31 बोर के 50 राउंड, 6.17 एमएम के 28 जिंदा कारतूस, तीन डेटोनेटर और दो बायोफेंग स्कैनर भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि नक्सली लंबे समय तक संचालन के लिए हथियारों और संचार संसाधनों का भंडारण कर रहे थे।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन और खुफिया सूचनाओं के प्रभावी उपयोग से नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाने अब लगातार उजागर हो रहे हैं। हथियारों के साथ-साथ नकदी की बरामदगी इस बात का संकेत है कि सुरक्षा बल अब नक्सलियों की सैन्य क्षमता के साथ-साथ उनके आर्थिक संसाधनों को भी व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में इसी प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सुरक्षा बलों का उद्देश्य नक्सलियों के जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक सामग्री और आर्थिक संसाधनों को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि क्षेत्र में शांति और विकास का वातावरण मजबूत हो सके।

नारायणपुर में हुई यह दोहरी कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।टेकला जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी, तोयामेटा जंगल से 24 लाख रुपए नकद मिलने से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है।

बस्तर में अब महिला सशक्तिकरण पर जोर

राजवाड़े ने कहा- आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों को रोजगार से जोड़ना फोकस

नक्सलवाद खात्मे के बाद अब आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के लिए विशेष पहल, महिला-बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाने की कवायद

जगदलपुर। बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर प्रभाव के बाद अब सरकार महिला सशक्तिकरण को नई प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बस्तर दौरे पर रहीं।

यहां उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, वृद्धाश्रमों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य संस्थानों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री ने विशेष रूप से उन महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है।

उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। विभाग उनके लिए स्वरोजगार, कौशल विकास और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू करेगा। ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। मंत्री राजवाड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनें बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद का खात्मा नहीं, बल्कि शांति और विकास के माहौल में महिलाओं को सम्मानजनक और सशक्त जीवन उपलब्ध कराना है।

कांकेर में बीएमओ को हटाने की मांग पर 7 घंटे स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर बैठे रहे कर्मचारी

कांकेर। जिले में स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ डॉ. शशांक गुप्ता के खिलाफ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। साथी कर्मचारी के निलंबन, कथित मनमानी और दुर्व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का घेराव कर 7 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी लगातार बीएमओ को हटाने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा समझाइश के बाद भी कर्मचारी पीछे नहीं हटे। आखिरकार प्रशासन की ओर से 15 दिनों के भीतर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन की ओर से उन्हें 15 दिनों के भीतर जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन तो खत्म हो गया है।

कबीरधाम के धान खरीदी केंद्रों में फिर मिली गड़बड़ी

अब तक 6 पर दर्ज हुई एफआईआर, भौतिक सत्यापन में सामने आई चोरी

कबीरधाम। कवर्धा जिले में धान खरीदी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के तीन धान उपार्जन केंद्रों में संयुक्त जांच के दौरान लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। मामले में प्रशासन ने तीनों केंद्र के प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने इस बहुचर्चित धान घोटाले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। जिले में अब तक कुल छह धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ अन्य केंद्रों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संयुक्त जांच टीम ने विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान सहसपुर लोहारा, बासिझोरी और बिरनपुर धान खरीदी केंद्रों

का औचक निरीक्षण किया।भौतिक सत्यापन में सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर मिला। जांच के दौरान तीनों केंद्रों से कुल 2441.92 क्विंटल धान और 21 हजार 982 नग खाली बारदाना गायब मिले।

इस गड़बड़ी से शासन को लगभग 81 लाख 19 हजार 502 रुपए की आर्थिक क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जांच में सहसपुर लोहारा समिति के प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभारी सहित संबंधित कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। टीम को कई ऐसे तौल पत्र भी मिले, जिनमें केवल किसानों के हस्ताक्षर थे, जबकि धान खरीदी प्रभारी, फड़ प्रभारी और तौलकर्ता के हस्ताक्षर वाले कॉलम खाली छोड़े गए थे। प्रारंभिक जांच में दस्तावेजों में हेरफेर कर अनियमितता किए जाने की आशंका जताई गई है।

ऑनर किलिंग का खुलासाः लव मैरिज से नाराज पिता ने भाइयों के साथ मिलकर की बेटी को मार डाला, खेत में फेंकी लाश

महासमुंद। जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में 17 जून को ग्राम तुरेंगा के खेत में मिले युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि युवती के अपने पिता, चाचा और बड़े पिता ने मिलकर की थी। मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है।

ग्राम तुरेंगा में एक खेत में युवती का शव मिला था। शव के गले और शरीर पर धारदार हथियार के कई निशान थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सोशल मीडिया, तकनीकी साक्ष्यों और लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मृतका की पहचान बागबाहरा निवासी रानी कुमारी के रूप में हुई। बाद में उसके पति ने शव की पहचान की।पुलिस जांच में सामने आया कि रानी ने परिवार की इच्छा के खिलाफ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और जांच आगे बढ़ी तो आरोपी घर के ही लोग निकले। प्रेम विवाह से ही नाराज होकर युवती के पिता उमेश सिंह, चाचा दिनेश सिंह और बड़े पिता राजेश सिंह ने उसकी हत्या की साजिश रची।

आरोप है कि तीनों आरोपी रानी को अपने साथ ले गए और ग्राम तुरेंगा के एक सुनसान खेत में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को वहीं फेंककर फरार हो गए।पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर गुजरात के सूरत में दबिश देकर मुख्य आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना के समय पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है।

गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सनसिटी क्षेत्र में कार-बाइक की टक्कर में दो पत्रकार घायल

डोंगरगढ़। राजनादगांव के सनसिटी क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो पत्रकार घायल हो गए। एक के पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। आरोप है कि मौके पर कार चालक ने पत्रकारों को कथित तौर पर कुचलने की कोशिश की। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक कार्यक्रम की कवरेज के बाद पत्रकार योगेश साहू और सौरभ अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सनसिटी के पास एक तेज रफ्तार सफेद रंग की ब्रेजा कार (क्रमांक CG 04 NE 1199) ने अचानक सामने आ गई, जिससे बाइक सवार जा टकराए। हादसे में पत्रकार सौरभ के पैर में गंभीर चोट आई है। पत्रकारों का आरोप है कि जब उन्होंने चालक को मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश की तब कार से कई बार कुचलने का प्रयास किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से पत्रकार की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।

पटवारी और बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

बिलासपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर एक पटवारी और विद्युत विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की कार्रवाई के बाद अब सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर जिले के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का अलम है, कई विभागों में बिना रिश्वत लिए काम नहीं हो रहा है। दो अलग-अलग क्षेत्रों में एसीबी को शिकायत मिली कि काम के एवज में पैसा मांगा जा रहा है, एसीबी ने योजना बनाई और कार्रवाई शुरू की। पहली कार्रवाई रतनपुर तहसील के लालपुर हल्का में पदस्थ पटवारी भानु चंद्राकर के खिलाफ की गई। एसीबी के अनुसार पटवारी ने जमीन का नक्शा एवं बटांकन कराने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी पटवारी को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

कलेक्ट्रेट में प्राईवेट स्कूल के शिक्षक व अभिभावक का प्रदर्शन

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में निजी स्कूलों ने पुस्तक वितरण में देरी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कोरबा जिले में भी अशासकीय विद्यालयों के संचालक और शिक्षकों ने कई मांगों को लेकर कलेक्टोरेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अशासकीय विद्यालय संघ ने राज्य शासन पर प्राइवेट स्कूलों के साथ उपेक्षा और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। दरअसल उनका कहना है कि निजी विद्यालयों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराए जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा निजी विद्यालयों को पुस्तकों के लिए कई बार बिलासपुर बुलाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पुस्तकें नहीं मिल पातीं और स्कूल प्रतिनिधियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।इस अवस्था के कारण विद्यालय प्रबंधन को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ के आह्वान पर जिले के विभिन्न अशासकीय विद्यालयों के संचालक, प्राचार्य व शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।

एचसी ने कलेक्टर को शिकायत पर सुनवाई के दिए निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट में डोंगरगढ़ के बहुचर्चित परिक्रमा पथ निर्माण मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कलेक्टर राजनांदगांव को पीड़ित याचिकाकर्ता के शिकायत पत्र पर सुनवाई का अवसर देते हुए परीक्षण कर निराकरण किए जाने का निर्देश जारी किया है। बता दें, कि याचिकाकर्ता की कृषि भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित करने के प्रस्ताव एवं प्रस्तुत शिकायत पत्र पर विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। दरअसल, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के अंतर्गत बुधवारी पारा वार्ड नंबर 19 निवासी फहीम अख्तर ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि, उसकी कृषि भूमि ग्राम छीरपानी पटवारी हल्का नंबर 29 खसरा नंबर 196/2 में स्थित है। कुछ दिन पूर्व जानकारी मिली कि, उसके उक्त खसरा नंबर की भूमि को प्रस्तावित डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित किए जाने कार्रवाई जारी है। जबकि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई लिखित या मौखिक सहमति नहीं दी थी।

सड़क बाधितकरनेवाले 20 दुकानदारों पर कार्रवाई

रायगढ़। निगम प्रशासन द्वारा नाले की सफाई बेहतर हो इसके लिए शहर को अतिक्रमण मुक्त एवं यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से संजय मार्केट क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सड़क बाधित करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर सार्वजनिक मार्ग पर सामान रखकर आवागमन बाधित करने वाले 20 प्रतिष्ठानों पर कुल 22,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। कार्रवाई के दौरान अलिना फूड वियर पर 1,000 रुपये, दिलावर शूज पर 1,000 रुपये, क्वालिटी स्टोर पर 2,000 रुपये, सुरेश गार्मेंट पर 1,000 रुपये, सहेली ड्रेसेज पर 1,000 रुपये, हरिश मेहर पर 1,000 रुपये, शूज हाउस पर 1,000 रुपये, मैफुल ड्रेसेज पर 1,000 रुपये, चाँद शूज पर 1,000 रुपये, अंकित सेल पर 2,000 रुपये, बाम्बे फैशन बाजार पर 2,000 रुपये, रविंद्र पर 500 रुपये, शूज गैलरी पर 1,000 रुपये, गुजराल मेडिकल पर 1,000 रुपये, गेलेक्सी बैग पर 1,000 रुपये, ग्रान्ड शूज पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

ग्रामीणों ने रखा पक्ष, निष्पक्ष जांच और फिर से सीमांकन की मांग

ग्रामीणों ने कहा- राजस्व अभिलेखों में त्रुटि ठीक करने कई बार ज्ञापन सौंप चुके

जगदलपुर। बस्तर जिले के करपावंड भूमि विवाद मामले में अब ग्रामीणों और सर्व आदिवासी समाज ने भी खुलकर अपना पक्ष रखा है। जिला पत्रकार संघ भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ग्रामीणों ने दावा किया कि भूमि विवाद को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से राजस्व अभिलेखों में कथित त्रुटियों के सुधार और विवादित भूमि के निष्पक्ष सीमांकन की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। ग्रामीण बंशीधर ने

बताया कि ग्रामीणों ने उस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जिसमें खसरा क्रमांक 567/2 की भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व अमला और पुलिस बल पहुंचा था। उनका कहना है कि गांव के जिम्मेदार लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों, कोटवार या पुजारी को कार्रवाई की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। ग्रामीणों का दावा है कि यदि पहले सूचना देकर सभी पक्षों की मौजूदगी में सीमांकन और कार्रवाई की जाती तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि जिस भूमि का सीमांकन करवाया जा रहा था। वह निजी भूमि नहीं थी। जिस भूमि पर करीब 50-60 वर्षों से ग्रामीण काबिज हैं। सर्व आदिवासी युवा प्रभाग के सदस्य लखेश्वर बघेल ने कहा कि ग्राम करपावंड में बंदोबस्त के दौरान तैयार किए गए नक्शों और वर्तमान राजस्व अभिलेखों में कई विसंगतियां हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने और वर्तमान खसरों के बीच भूमि के रकबे और स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिससे लगातार विवाद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जा चुका है।

अब तक पूरी विवादित भूमि का निष्पक्ष सीमांकन नहीं कराया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द विवादित भूमि का सीमांकन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे।

किरणमयी की अध्यक्षता में कोरबा में महिला आयोग की जनसुनवाई

कोरबा। जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला आयोग की जनसुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ। किरणमयी नायक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से जुड़े केस की सुनवाई की गई। गुरुवार को 26 केस रखे गए थे जिसमें कुछ मामलों में सख्त आदेश भी जारी किए गए।जनसुनवाई के दौरान लगभग 300 नगर सैनिकों की ओर से हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण शिकायत पर आयोग ने गंभीरता से सुनवाई की।

शिकायत में नगर सेना कोरबा के तत्कालीन कमांडेंट पर महिला नगर सैनिकों के साथ अनावश्यक सख्ती बरतने, सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के

आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में पूर्व में नगर सैनिकों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। मामले में अब तक आंतरिक परिवाद समिति (ढृष्टष्ट) की जांच नहीं होने पर आयोग ने नगर सेना कमांडेंट, कोरबा को निर्देशित किया है। जिसमें कहा है कि 2 माह के भीतर सभी संबंधित नगर सैनिकों और संबंधित अधिकारी के बयान दर्ज कर आईसीसी के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने ष्टस्श्वक्क के कार्यपालन अभियंता को जमकर फटकार लगाई। उन पर एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उनकी माता कैंसर पेशेंट है लेकिन उनकी देखभाल के लिए छुट्टी नहीं दी गई। साथ ही मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। ष्टक्रभी खराब किया गया। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि आपकी शिकायतें बार-बार हुई हैं। यहां लगता है कि आपके साथ कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है। महिला को राहत देते हुए आयोग ने उच्च अधिकारियों से दोबारा सीआर तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही कार्यपालन अभियंता के ट्रांसफर का भी निर्देश दिया गया है। एक प्रकरण में पति की ओर से पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण की उपेक्षा किए जाने पर आयोग ने सुनवाई। इसमें पति को प्रतिमाह 5000 रुपये भरण-पोषण राशि देने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के नाम से खरीदे गए मकान को लेकर उपजे विवाद में आयोग ने संबंधित पक्ष को एक माह के भीतर मकान खाली करने की समझाइश दी है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने समिति का गठन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन, सुझाव और प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई अध्यक्ष होंगी और 5 सदस्यीय समिति ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बन जाने से सभी धर्मों के पर्सनल लॉ होंगे समाप्त होंगे।

8 लोगों की संदिग्ध मौतः कांग्रेस ने गृहमंत्री से की सीबीआई जांच की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कसडोल में 8 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने एक ओर जहां गांव के ही एक आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी ओर लोग तंत्र विद्या की आशंका जता रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने गृहमंत्री विजय शर्मा से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। विधायक संदीप साहू का कहना है कि सरकार सीबीआई या एसआईटी से मौतों की जांच कराए। स्थानीय लोग लगातार तंत्रविद्या की आशंका जता रहे हैं। आखिर कितने लोगों की मौत हुई और कैसे हुई इसकी जांच की जाए। बता दें कि खर्वे गांव में फरवरी से 14 मई तक 8 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। ग्रामीणों ने गांव के ही राम सहाय जायसवाल पर शक जताते हुए जांच की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ में पूरा खुलासा कर दिया। आरोपी ने बताया कि छोटी-छोटी बातों, गाली-गलौज, अंधविश्वास और पुरानी रंजिश के चलते उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। सभी लोगों को उसने शराब में सुहागा मिलाकर मौत के घाट उतारा था। वहीं अब लोग मौत के पीछे तंत्र विद्या की आशंका जता रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने सरकार से सीबीआई या एसआईटी से मौतों की जांच कराने की मांग की है।

जैविक सब्जी के उत्पादन और एप्पल की खेती से बनाई नई पहचान

रायपुर। नगर पंचायत मल्हार के प्रगतिशील

किसान श्री जदुनंदन वर्मा ने जैविक खेती और नवाचार के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वे एक एकड़ में जैविक सब्जियों की खेती कर सालाना लगभग दो लाख रुपये की आमदनी अर्जित कर रहे हैं। वहीं आधा एकड़ में जैविक एप्पल की खेती कर उन्होंने क्षेत्र के किसानों के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। पिछले लगभग दस वर्षों से वे पूरी तरह जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। उनकी सफलता अन्य किसानों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। श्री जदुनंदन वर्मा बताते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। वे गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत तथा अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर खेती करते हैं। इससे उत्पादन लागत में कमी आई है, फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और मिट्टी की उर्वरता भी लगातार बढ़ी है। श्री जदुनंदन वर्मा ने लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले आधा एकड़ भूमि में जैविक एप्पल के पौधे लगाए थे। पिछले दो वर्षों से उन्हें एप्पल का उत्पादन मिल रहा है। उनके खेत में तैयार होने वाले जैविक एप्पल की मांग इतनी बढ़ गई है कि ग्राहक स्वयं उनके खेत पहुंचकर फल खरीदकर ले जाते हैं। इससे उन्हें बेहतर मूल्य मिलने के साथ जैविक उत्पादों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है।

नई सोच, नई तकनीक, नई उम्मीद : नैनो उर्वरकों से सशक्त हो रही खेती

रायपुर। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने

और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में नैनो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोरबा जिले के ग्राम जपेली निवासी कृषक श्री रतन सिंह इसका एक प्रेरक उदाहरण हैं। लगभग साढ़े चार एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले श्री रतन सिंह के लिए कृषि ही आय का प्रमुख साधन है। वर्षों से खेती कर रहे रतन सिंह ने बदलते समय के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया और पिछले वर्ष से अपने खेतों में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का उपयोग शुरू किया। श्री रतन सिंह बताते हैं कि प्रारंभ में उन्होंने नैनो उर्वरकों को लेकर जानकारी प्राप्त की और कृषि विभाग के मार्गदर्शन में इसका उपयोग किया।

वित्त मंत्री ने मैक कॉलेज के राष्ट्रीय सम्मेलन में युवाओं से कहा- बदलती तकनीक के अनुरूप स्वयं को करें तैयार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने वाले ही भविष्य का नेतृत्व करेंगे : चौधरी

एआई से डरने की नहीं, उसे अवसर में बदलने की है जरूरत

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज (एमएआईसी) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन "Artificial Intelligence & Digital Transformation: Opportunities, Challenges and Future Impact" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर युवाओं का आह्वान किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर मानें।

अपने संबोधन में मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आज पूरी दुनिया तेजी से ज्ञान, तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत का स्वर्णिम इतिहास भी ज्ञान, शिक्षा और नवाचार की नींव पर खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगभग 1600 वर्षों तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए रहा क्योंकि यहां शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को सर्वोच्च स्थान दिया गया।

मंत्री श्री चौधरी ने युवाओं से कहा कि आज दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति और उद्यमी वे हैं जिन्होंने नए विचारों और नवाचार के बल पर अपनी पहचान बनाई है। एलन मस्क, एनवीडिया और एप्पल जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज तकनीक की शक्ति इतनी बड़ी हो चुकी है कि कई टेक्नोलॉजी कंपनियों का मूल्यांकन अनेक देशों की अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। इसलिए युवाओं को समय रहते तकनीकी परिवर्तन को समझकर स्वयं को उसके अनुरूप तैयार करना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि जो एआई को अपनाएगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। जो इससे दूर भागेगा, वह प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि हर तकनीकी परिवर्तन चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन वही परिवर्तन नए अवसर भी पैदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि युवा इन अवसरों का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि एआई कई कार्यों को सरल बना सकता है, लेकिन मानवीय संवेदनशीलता, करुणा और मानवीय स्पर्श का विकल्प कभी नहीं बन सकता। इसलिए युवाओं को ऐसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए जहां मानवीय मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, नर्सिंग और अन्य सेवा क्षेत्र।

मंत्री श्री चौधरी ने युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल नौकरी तलाशने तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार और उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ें तथा विश्वस्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां स्थापित करने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और पूरी दुनिया में भारतीय तकनीकी नेतृत्व का लोहा माना जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत ञ्च2047 के विजन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ सरकार भी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 पर कार्य कर रही है। इस दिशा में नवा रायपुर को उभरते तकनीकी और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां सेमीकंडक्टर यूनिट, एआई डाटा सेंटर तथा ट्रिपल आईटी में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है।

कार्यक्रम के अंत में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज प्रबंधन, आयोजकों एवं सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के युवा नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।

नवा रायपुर को मिली आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की नई सौगात

वित्त मंत्री चौधरी ने किया सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ

रायपुर। नवा रायपुर के सेक्टर-9 में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। नवा रायपुर में इस अत्याधुनिक अस्पताल की शुरुआत से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय जिन चुनौतियों की चर्चा होती थी, आज उन्हें पीछे छोड़ते हुए राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश और आधुनिक अस्पतालों की स्थापना से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के प्रयासों और निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना लगातार मजबूत हो रही है, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 50 बिस्तरों वाले सरोज सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल के संचालन से नवा रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रबंधन तथा बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही।

डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ मामला

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को शिकायत पर सुनवाई के दिए निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट में डोंगरगढ़ के बहुचर्चित परिक्रमा पथ निर्माण मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कलेक्टर राजनांदगांव को पीड़ित याचिकाकर्ता के शिकायत पत्र पर सुनवाई का अवसर देते हुए परीक्षण कर निराकरण किए जाने का निर्देश जारी किया है। बता दें, कि याचिकाकर्ता की कृषि भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित करने के प्रस्ताव एवं प्रस्तुत शिकायत पत्र पर विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा है।

दरअसल, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के अंतर्गत बुधवारी पारा वार्ड नंबर 19 निवासी फहीम अख्तर ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि, उसकी कृषि भूमि ग्राम छीरपानी पटवारी हल्का नंबर 29 खसरा नंबर 196/2 में स्थित है। कुछ दिन पूर्व जानकारी मिली कि, उसके उक्त खसरा नंबर की भूमि को प्रस्तावित डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित किए जाने कार्रवाई जारी है। जबकि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई लिखित या मौखिक सहमति नहीं दी थी। वर्तमान में याचिकाकर्ता की उक्त भूमि पर सड़क निर्माण की कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है और याचिकाकर्ता को ज्ञापन जारी कर उसके उक्त कृषि भूमि को मनमाने अत्यधिक कम कीमत पर खरीदने के संबंध में शासन के द्वारा प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता अपनी उक्त कृषि भूमि को बेचना नहीं चाहता और ना ही उसके बदले में किसी प्रकार का मुआवजा चाहता है।

याचिकाकर्ता ने आपत्ति करते हुए कलेक्टर जिला राजनांदगांव के समक्ष एक शिकायत पत्र भी दिया था, कि उक्त प्रस्तावित परिक्रमा पथ के लिए किसी भी प्रकार से निजी भूमि अधिग्रहित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्रस्तावित परिक्रमा पथ के आसपास ही पर्याप्त शासकीय एवं राजस्व भूमि उपलब्ध है, जिसके माध्यम से सड़क का निर्माण किया जा सकता है। स्वीकृत नक्शे के विरूद्ध निजी भूमि का चयन किया जाना अनुचित है। यदि सड़क निर्माण उपलब्ध राजस्व भूमि से किया जाता है तो शासन को भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान में होने वाले अतिरिक्त व्यय से बचाया जा सकता है, साथ ही परिक्रमा पथ के लिए पूर्व से ही मार्ग बना हुआ है।

नगरीय निकायों में एल्डरमैन की होगी नियुक्ति

■ **विष्णु देव साय सरकार ने जारी की सूची**

रायपुर। स्थानीय निकाय के कामकाज में पारदर्शिता लाने और जनहित के फैसलों को मजबूत बनाने का काम एल्डरमैन करते हैं। एल्डरमैन अपने अनुभव से जनहित में अपनी सूझबूझ भरी राय भी देते हैं। उनकी राय और मार्गदर्शन से विकास के कामों में तेजी और पारदर्शिता आती है। इसी पारदर्शिता के कामों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है।

प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों के साथ ही स्थानीय निकायों में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज होने की उम्मीद है।

काफी समय से एल्डरमैन नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए नामों को अंतिम रूप देते हुए नियुक्ति सूची जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त सदस्य स्थानीय निकायों की बैठकों और विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभाएंगे।

एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद स्थानीय निकायों में विकास योजनाओं, जनहित के प्रस्तावों और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एल्डरमैन नियुक्तियों के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नियुक्तियों को स्थानीय संगठन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एल्डरमैन नगर निगम की बैठकों में चर्चा और प्रस्तावों पर राय तो दे सकते हैं, लेकिन निगम के सामान्य फैसलों या महापौर के चुनाव में इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।

मुख्यमंत्री की पहल से जशपुर की महिलाएं बनेंगी ड्रोन दीदी

■ **रायपुर में ले रहीं आधुनिक ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण, किसानों तक पहुंचाएंगी तकनीक आधारित कृषि सेवाएं**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में जशपुर जिले की स्व-सहायता समूहों की महिलाएं नई पहचान बना रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जिले की चयनित महिलाएं इन दिनों रायपुर स्थित आईटीएम विश्वविद्यालय में ड्रोन संचालन एवं रिमोट पायलटिंग का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

यह प्रशिक्षण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के साथ उन्हें कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं देने के लिए दक्ष बन रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन दीदियों को ड्रोन की तकनीकी संरचना, सुरक्षित उड़ान संचालन, रिमोट पायलटिंग, फसलों में उर्वरक एवं कीटनाशकों का वैज्ञानिक छिड़काव, ड्रोन के रखरखाव तथा कृषि क्षेत्र में उसके व्यावहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ये ड्रोन दीदियां जशपुर जिले के किसानों को ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य कृषि कार्यों की सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे कृषि कार्य कम समय में, कम लागत पर और अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में जशपुर प्रवास के दौरान प्रशिक्षण के लिए रवाना हो रही ड्रोन दीदियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पूर्व 17 अप्रैल 2026 को रणजीता स्टेडियम में आयोजित %लखपति दीदी% कार्यक्रम के दौरान ड्रोन दीदी एवं उन्नत सॉयल टेस्टिंग मशीन भी प्रदान की गई थी।

उप संचालक कृषि, जशपुर के अनुसार प्रशिक्षण के बाद ड्रोन दीदियां जिले के विभिन्न विकासखंडों में किसानों को तकनीक आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। इससे खेती में समय की बचत, लागत में कमी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग का विश्वास है कि यह पहल जशपुर में तकनीक आधारित कृषि को नई गति देने के साथ महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक सशक्तता और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर मचा बवाल, सत्ता बचाने के लिए भाजपा का प्रपंच : भगत

डिप्टी सीएम साव ने कहा- गलत प्रचार करती है कांग्रेस, केदार गुप्ता बोले- सुरक्षित रहेंगी आदिवासियों की परंपराएं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता याने यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की तैयारियों के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत भगत ने इसे सत्ता बचाने के लिए भाजपा का प्रपंच करार दिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हर बात पर गलत प्रचार करने का आरोप मढ़ा है। वहीं भाजपा नेता केदार गुप्ता ने प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद भी आदिवासी समाज की परंपराओं के पूरी तरह सुरक्षित रहने का भरोसा दिलाया है।

समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यूसीसी देश के लिए एक पेचीदा विषय है। भारत विविधताओं का देश है, जहां सभी पर एक कानून उचित नहीं है। जंगल में रहने वाले आदिवासी को यूसीसी की जानकारी तक नहीं है, ऐसे में जनता पर यूसीसी का सकारात्मक असर नहीं होगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। रही बात अमरजीत भगत के बयान की तो कांग्रेस पार्टी हर बात पर भ्रम फैलाने का काम करती है। यूसीसी से आदिवासी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

वहीं केदार गुप्ता ने कहा कि अमरजीत भगत आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी आदिवासियों की समझ पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा बेहद समृद्ध है। यूसीसी लागू होने पर भी आदिवासी समाज की परंपराएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। यूसीसी लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में भी मददगार होगा। अगर कांग्रेस इन सब बातों को समय रहते समझ जाती, तो आज उसकी यह दुर्गति नहीं होती।

पूर्व मंत्री अमरजीत ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के संबंध में कहा कि इससे भाजपा का बीपी बढ़ेगा। भाजपा कांग्रेस की विचारधारा से घबराई हुई है। भाजपा नेता डॉक्टरों से बीपी चेक करा कर देखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए भाजपा बेचैन है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमीनी लड़ाई तेज कर दी है। प्रशिक्षण के बाद जिलाध्यक्षों का नया कलेवर दिखेगा।

भगत के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बीपी किसका बढ़ा हुआ है, यह प्रदेश की जनता बता देगी। देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी पर बीजेपी की सरकार है। इनके गठबंधन के दल इनको छोड़कर जा रहे हैं। बीपी तो कांग्रेस का बढ़ा हुआ है।

वहीं बीपी बढ़ने वाले बयान पर केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा का ब्लड प्रेशर, शुगर और मेंटल लेवल एक जैसा रहता है। कांग्रेस को पूरा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। 22 राज्यों में उन्हें खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बात भूपेश बघेल के बयान में दिखता है, जब वह बार-बार कहते है 'कका अभी जिंदा है।' भूपेश बघेल दीर्घायु हों, चिरायु हों, पर अमरजीत भगत को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस का स्वास्थ्य इससे पता चल रहा है।

कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने प्रदेश में खाद-बीज के संकट के साथ मानसून की बेरुखी का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। कृषि पर आधारित जीवन है। अगर खेती नहीं हो रही है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। किसान को खाद-बीज और पानी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन इस सरकार में खाद नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है। किसान आखिर कहां जाएगा। पूरी परिस्थिति प्रदेश के किसानों के विरुद्ध है। कुछ करने में सरकार निसहाय दिख रही है।

इस विषय पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने खाद बीज के वितरण की पूरी व्यवस्था की है। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। किसान समझ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने किसानों को परेशान किया, आज किस मुँह से किसानों की बात कर रहे हैं।

निश्चिंत राकांपा को लेकर शिवसेना की चिंता

अमिताभ श्रीवास्तव

अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों की वर्षगांठ के दौरान एकजुटता का प्रदर्शन आंखों से ओझल नहीं हुआ था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राऊत ने राकांपा (शरद पवार गुट) को कांग्रेस में विलय का सुझाव दे दिया है। इसके साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विघटन को देख उन्होंने कांग्रेस से अलग हुए सभी दलों के समक्ष वापसी का विचार रख दिया। हालांकि उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए राकांपा (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने पहले तो संजय राऊत को अपने बड़े भाई की तरह बताया। फिर मजबूत लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार बताकर सुझाव को अच्छा बता दिया। किंतु किसी किस्म की सहमति या फिर सोच व्यक्त नहीं की। इसी प्रकार उनकी पार्टी के विधायक रोहित पवार के अनुसार तृणमूल कांग्रेस और राकांपा प्रमुख विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। मगर उसकी संभावना या प्रयास का विचार शीर्ष नेताओं पर छोड़ दिया गया है। यदि अतीत में देखा जाए तो ममता बनर्जी ने एक जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, जबकि शरद पवार ने 10 जून 1999 को कांग्रेस से अलग होकर राकांपा का गठन किया था। दोनों का सीधा विरोध या नाराजगी पार्टी आलाकमान से थी। दूसरी ओर दोनों ही दलों ने पिछले 27-28 सालों में जितना सत्ता सुख भोगा, शायद उतना उन्हें कांग्रेस में रहते हुए मिलना असंभव था। यही नहीं, दोनों ही पार्टियों ने नए नेताओं की एक नई फौज खड़ी की, जिसे तब तैयार करना आसान नहीं होता। इसलिए संकट की घड़ी में दोनों की मजबूरी को कमजोरी मानना सहज नहीं होगा। 28 साल पहले जब तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था, तब ममता बनर्जी का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना था। जिसके लिए कांग्रेस उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रही थी। बाद में आलाकमान से नाराजगी दिखाकर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जमीनी स्तर से तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। डटकर मुकाबला कर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका। यही नहीं, लगातार तीन बार बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। मोदी युग में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से दो-दो हाथ कर अपनी जड़ें हिलने नहीं दीं। आरंभ में संयम से काम लेते हुए वर्ष 1998 से 2011 तक सत्ता पाने का इंतजार किया। कभी केंद्र में भाजपा और कांग्रेस का साथ दिया। राज्य में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। फिर एकछत्र राज स्थापित किया। दूसरी ओर 10 जून 1999 को स्थापना के बाद राकांपा ने कभी अकेले राज करने की कोशिश नहीं की। पार्टी नेता शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ी थी, मगर महाराष्ट्र या केंद्र में सत्ता का अवसर आने पर तालमेल में उन्होंने कोई संकोच नहीं दिखाया। राकांपा का विस्तार अपने स्थान पर हुआ, किंतु केंद्र में कुछ पदों के अलावा राज्य में उपमुख्यमंत्री पद से अधिक कुछ नहीं मिला। विधानसभा या लोकसभा की सीटों में भी उसने कभी कांग्रेस से बड़ी बढ़त नहीं हासिल की। राकांपा के समक्ष पहली समस्या राज्य में देवेंद्र फडणवीस सरकार के आने के बाद उत्पन्न हुई, जिसमें पहली बार पांच साल विपक्ष में बैठना पड़ा। उसके बाद पार्टी में टूट के आसार बने, लेकिन वे अधिक दिन नहीं टिके। फिर कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार बनी, जिसमें भी उसे सत्ता सुख मिला। लगभग ढाई साल बाद सरकार का पतन हुआ। शिवसेना दो भागों में विभाजित हो गई। कुछ दिन में राकांपा में भी फूट पड़ी तथा एक गुट नई सरकार में शामिल हो गया।

डील पक्की... लेकिन एक शर्त पर!

अभिनय आकाश

भारत और अमेरिका के बीच में चल रहे ट्रेड टॉक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। या फिर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने अब अमेरिका की तरफ टेबल टर्न कर दिया है। अभी तक भारत अमेरिका के ऊपर यह शर्त लगा रहा था कि हम तब तक डील साइन नहीं करेंगे जब तक अमेरिका भारत को बाकी देशों के मुकाबले में कम टैरिफ ऑफर नहीं करेगा। अब भारत ने उसके साथ में एक और बहुत ही बड़ी डिमांड कर दी है। जिसमें कि भारत के द्वारा सनसेट क्लॉज़ की डिमांड की गई है। यह एक ऐसा नया और बड़ा दांव है, जिसे भारत ने अमेरिका के साथ चल रही इस महा-ट्रेड डील की मेज पर पटक दिया है! तो यह क्लॉज़ कुछ और नहीं, बल्कि भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। रिपोर्ट की मानें तो नई दिल्ली का वाशिंगटन से सीधा कहना है कि देखिए बॉस, आपकी आर्थिक नीतियां और फैसले इतनी तेजी से बदलते हैं कि अब हम केवल आपके खोखले वादों और आश्वासनों के भरोसे नहीं बैठ सकते! जिस रफ्तार से पिछले कुछ समय में अमेरिकन पॉलिसीज में बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, उसे देखते हुए इस ट्रेड डील में एक सनसेट क्लॉज़ का होना अब बेहद अनिवार्य हो चुका है और इसके बिना भारत इस डील में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है यह सनसेट क्लॉज़? भारत को अचानक इस क्लॉज़ को लाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर यह डील में शामिल होता है, तो इससे भारत को क्या-क्या बड़े फायदे होने वाले हैं? इन सभी कूटनीतिक और आर्थिक पहलुओं का आज हम एमआरआई स्कैन करेंगे।

सनसेट क्लॉज़ एक ऐसा प्रावधान है जो कि कई सारे समझौतों में, कई सारे एग्रीमेंट्स में देखने को मिलता है और यह मूलत: इंश्योरेंस मैकेनिज्म यानी सुरक्षा कवच की तरह फ्यूचर पॉलिसी चेंजेस के खिलाफ काम करता है। इसको बहुत ही सरल शब्दों में कहे तो एक तरीके का सुरक्षा कवच होता है। मतलब कि अगर आगे चलकर हालात बदल जाते हैं। दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी किसी भी तरीके के बदलाव का ऐलान कर देती है, तो दोनों देशों को समझौते की शर्तों पर फिर से बैठकर के रीनेगोशिएट करना पड़ता है। फिर से बैठकर के बातचीत करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आज

भारत और अमेरिका किसी एग्रीमेंट पर साइन कर लें और साल भर बाद अमेरिका उठकर कह दे कि भईया, हम तो अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं, लेकिन जो पुरानी डील साइन हुई थी, वो आप चुपचाप वैसे ही मानते रहिए! भारत का बिल्कुल साफ और कड़ा स्टैंड है कि जी नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा! अगर कल को अमेरिका अपनी नीतियां बदलता है, तो उस मनमानी और बड़े नीतिगत झटके से खुद को बचाने के लिए ही भारत इस डील में सनसेट क्लॉज़ को जोड़ने पर अड़ा हुआ है। यह क्लॉज़ भारत के लिए वो कानूनी ढाल है, जो अमेरिका को अपनी शर्तों से पीछे हटने पर दोबारा बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर देगी!

भारत द्वारा इस समय व्यापार समझौते में रिव्यू मैकेनिज्म या सनसेट क्लॉज (समीक्षा व समाप्ति शर्त) पर जोर देना, पिछले एक साल के दौरान अमेरिका के भीतर बदली आर्थिक नीतियों और अनिश्चितताओं से सीधा जुड़ा हुआ है। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं बाजार पहुंच, स्थिर टैरिफ दरों और नियमों के भरोसे पर आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब कोई देश अपनी नीतियां बार-बार बदलता है, तो ये सारे अनुमान कमजोर पड़ जाते हैं। अमेरिकी बाजार में हाल ही में हुए टैरिफ संशोधनों, कानूनी विवादों और नीतिगत बदलावों को देखते हुए नई दिल्ली अब केवल मौखिक आश्वासनों के भरोसे कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहती। असल चिंता व्यापार समझौते को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि भारत द्वारा बड़े नीतिगत वादे और निवेश कर दिए जाने के बाद अगर वाशिंगटन की परिस्थितियां अचानक बदल गईं, तो क्या होगा। यही वजह है कि भारत एक ऐसा सनसेट क्लॉज चाहता है जो भविष्य में किसी भी बड़े नीतिगत झटके के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करे और आर्थिक आधार बदलने पर दोनों देशों को नए सिरे से मेज पर बैठने का कानूनी अधिकार दे।

भारत की सोच पर असर डालने वाली एक अहम घटना 20 फरवरी को हुई। उस दिन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से एक फ़ैसला सुनाया, जिसने अमेरिका में टैरिफ़ तय करने के अधिकार से जुड़े कानूनी ढांचे को बदल दिया। इस फ़ैसले में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ आपसी द्विपक्षीय टैरिफ़ लगाने के लिए पहले जिस कार्यकारी कानून का इस्तेमाल किया जाता था, वह अधिकृत नहीं था; इस तरह टैरिफ़ तय करने की शक्तियाँ असल में कांग्रेस को वापस मिल गईं। इस फ़ैसले के अहम नतीजे निकले क्योंकि इसने उन धारणाओं को बदल दिया जिन पर पहले व्यापार से जुड़ी बातचीत आधारित थी। फ़ैसले के बाद, टैरिफ़ के एक ऐसे ढांचे की उम्मीद कम निश्चित हो गई जिसके बारे में पहले काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इसके बाद, अमेरिका टैरिफ़ के एक अलग ढांचे की ओर बढ़ गया, जबकि साथ ही वह व्यापार को लागू करने वाले अलग-अलग तरीकों पर भी निर्भर रहा। इनमें सबसे अहम हैं सेक्शन 301 के तहत होने वाली जांच, जो अमेरिकी व्यापार नीति का एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने मार्च में जांच शुरू की, जिसमें मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी (ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन क्षमता) और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया गया। इन जांचों में कई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और अगर वॉशिंगटन इस नतीजे पर पहुंचता है कि कुछ विदेशी नीतियां अमेरिकी व्यापार पर बुरा असर डाल रही हैं, तो इसके चलते व्यापार से जुड़े और भी कदम उठाए जा सकते हैं। भारत के लिए इससे अनिश्चितता पैदा होती है। भले ही आज टैरिफ में छूट को लेकर बातचीत हो जाए, लेकिन जांच या नीतिगत फैसलों के कारण भविष्य में होने वाले व्यापारिक कदमों से उन छूटों का व्यापारिक मूल्य बदल सकता है। इन जाँचों से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। इससे यह संकेत मिलता है कि ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भी टैरिफ से जुड़ी स्थिति में बदलाव जारी रह सकता है। सनसेट क्लॉज़ अमेरिका को अपने घरेलू ट्रेड कानूनों का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगा। बल्कि, यह भारत को एक औपचारिक मौका देगा कि अगर मूल आर्थिक समझौते में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो वह अपनी प्रतिबद्धताओं पर फिर से विचार कर सके।

टैरिफ (सीमा शुल्क) के मोर्चे पर, दोनों देशों के बीच चर्चा का मुख्य फोकस इस बात पर है कि भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाले शुल्कों को कैसे कम किया जाए और इसके साथ ही, भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों की पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए। अमेरिका विशेष रूप से भारत में अपने कृषि उत्पादों जैसे कि ट्री नट्स (बादाम, अखरोट आदि), ताजे फल, सोयाबीन तेल और पशु चारे (जैसे ज्वार या सोरघम) के लिए बड़े अवसरों और रियायतों की तलाश कर रहा है। दूसरी ओर, भारत अपनी रणनीति पर अड़े रहते हुए अपने उन क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं, जिनमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। बातचीत सिर्फ़ पारंपरिक सामानों के व्यापार तक ही सीमित नहीं है। ऊर्जा और टेक्नोलॉजी भी चर्चा के अहम हिस्से बन गए हैं। वॉशिंगटन अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहता है और साथ ही भारतीय बाज़ार में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों जिनमें डेटा-सेंटर हार्डवेयर और ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल हैं। उनके लिए अपनी पहुँच बनाना चाहता है। इसके बदले, भारत से उम्मीद है कि वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम करके अमेरिकी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी को और मजबूत करेगा। हालांकि, इन मौकों के साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत पांच साल की अवधि में 500 अरब डॉलर तक के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा कर सकता है। ऐसे वादों के लिए लंबी अवधि की योजना और खरीद के तरीकों में बड़े बदलावों की ज़रूरत होगी, जिसमें रूसी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना भी शामिल है। यही एक मुख्य कारण है कि भारत अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(निरुक्त 1 । 6 । 2-3) में यह सब प्ररुङ्ग विस्तारपूर्वक आता है। यही भाव यहाँ दिखाया गया है। ऐसे अर्थ ज्ञान-शून्य पुरुषों को दान, यज्ञ, श्राद्ध आदि में सम्मानित करना अवश्य वर्जित है यह तो हमारा सनातन सिद्धांत है। हमारे यहाँ दयानन्दी समाज की तरह- विश्वानि देव सवितः ! के स्थान में-

बीस वानिदे सरबत दूरीतानपरासवा

-बोलने वाले पञ्चम-अन्यथासिद्धों को भी वेदालङ्कार की उपाधि नहीं दी जा सकती?

पुराण शास्त्रों में किसी भी सद्ग्रन्थ की, तथा स्मृत्यादि में किसी ग्रन्थ विशेष के पाठकों की कहीं भी निन्दा नहीं की गई। विश्व भर की निन्दा का ठेका तो एकले दयानन्द जी और उनके चेले चाँटों के नाम सदा के लिये रिजर्व हो चुका है। यह करतूत सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों से, और सत्यवक्ता महात्मा गाँधी के शब्दों में दूसरे मजहबों की निन्दा करने वाले झगड़ालू समाजियों के व्यवहार से काफी विख्यात हो चुकी है।

आयुर्निर्णय

कई महाशय कहते हैं कि पुराणों में तथा रामायण महाभारतादि इतिहास ग्रन्थों में अनेक ऋषियों मुनियों+ का सहस्रों वर्ष तक तपश्चर्या करना एवं अनेक राजाओं का हजारों वर्षपर्यन्त राज्य करना लिखा है, जिससे तत्कालीन पुरुषों का इतनी बड़ी आयु वाला होना पाया जाता है, परन्तु वेद में %शतायुर्वे पुरुषः% आदि प्रमाणों के अनुसार मनुष्य की पूर्णायु केवल सौ वर्ष ही लिखी है, और प्रत्यक्ष में भी अधिक से अधिक इतनी ही आयु देखी जाती है। इसलिए पुराण प्रतिपादितै मनुष्यायु अवश्य ही अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है- हम इस विषय का कुछ विस्तारपूर्वक विवेचन करना आवश्यक समझते हैं जिससे कि सर्वसाधारण को आयुष्यविज्ञान का पूरा 2 बोध हो जाए।

क्रमशः ...

विश्व मधुमेह दिवस

कमलेश पांडेय

आम लोगों में मधुमेह (डायबिटीज) बीमारी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आईडीएफ यानी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे के लिए एक थीम चुनता है। इस वर्ष के लिए उनका मेन फोकस है- डायबिटीज केयर तक पहुंच: यदि अभी नहीं, तो कब?

देखा जाए तो गाँव से शहर की तरफ भागने के इस दौर में हम शहरी सुख-सुविधाओं और उन्नत तकनीकी का लाभ तो उठा पा रहे हैं, लेकिन शहरी भाग दौड़ के जीवन में विकसित हो रही अव्यवस्थित जीवनशैली और तनाव की वजह से मधुमेह बीमारी के शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि गांवों की तुलना में शहरी आबादी में

डायबिटीज के रोगी ज्यादा मिलते हैं।

इसलिए इस बीमारी को रोकने के लिए न केवल जनजागरूकता बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव भी बेहद जरूरी है। सच कहा जाए तो मधुमेह बीमारी में जागरूकता एवं बचाव की सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि मधुमेह का नियंत्रण तो किया जा सकता है, पर इसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता।

वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित छाबड़ा ने मधुमेह रोग के बारे में जानकारी देते हुए फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया कि बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ एवं बुजुर्गों- सभी आयु वर्ग में मधुमेह अब विश्व में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। खासकर भारतीय युवा आबादी में डायबिटीज के काफी रोगी हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

ऐसे में डाइबिटीज को यदि नियंत्रित ना किया जाये, तो इसका असर किडनी (गुर्दा), आँख, हृदय तथा ब्लड प्रेशर आदि पर पड़ता हैं। दरअसल, डायाबिटिज की बीमारी में शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है, जब शरीर में हार्मोन इन्सुलिन की कमी हो जाती है या इन्सुलिन का शरीर की क्रियाओं के साथ संतुलन बिगड़ जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि हमलोग सामान्यत: मधुमेह रोग से बचने के लिए चीनी खाना कम कर देते हैं, किंतु यह सही नहीं है। चीनी से ज्यादा हमें कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पराठे में चीनी नहीं होती, लेकिन उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में वह पराठा यदि किसी को डायबिटीज होने का खतरा बना हुआ है तो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

मधुमेह ग्रसित होने पर बैलेंस डाइट एवं एक साथ ज्यादा खाना खाने की बजाय 2-3 घंटे के अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा खाना खाना चाहिए। साथ ही दिन भर की एक उचित समय सारणी बनाएं तथा उसका पालन करें। यह मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए एक अच्छा उपाय है।

लोगों को उचित समय अंतराल में ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए एवं साल में एक बार 3 महीने की मधुमेह रोग की जानकारी देने वाले टेस्ट एचबीए1सी को भी कराते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज शुरू होने के कई लक्षण आरम्भ में दिखने लगते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।

दुनिया को क्या संदेश दे रहा है ईरान

एडवर्ड फिशमैन

अमेरिका और ईरान के बीच हाल में हुए अस्थायी शांति समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने, कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने और ईरान की उसकी संपत्तियों तक पहुंच बहाल करने पर सहमति बनी थी। साथ ही, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर वार्ता शुरू करने की भी घोषणा की गई थी। हालांकि, क्षेत्रीय तनाव कम होने के बजाय फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेबनान और अन्य मोर्चों पर इस्राइल की लगातार सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके सुरक्षा हितों की अनदेखी जारी रही, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य में नए प्रतिबंध लगा सकता है तथा टोल व्यवस्था दोबारा लागू कर सकता है।

भले ही युद्ध और प्रतिबंधों ने ईरान को सैन्य तथा आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका भौगोलिक प्रभाव अब भी उसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति बनाए हुए है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक पर उसका नियंत्रण उसे क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति में मजबूत सौदेबाजी की स्थिति प्रदान करता है। यदि मौजूदा तनाव जारी रहता है, तो होर्मुज एक बार फिर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख केंद्र बन सकता है। बेशक ट्रंप ने भी कहा है कि होर्मुज हमेशा के लिए टोल-फ्री रहेगा, लेकिन इस जलमार्ग पर ईरान की पकड़ ढीली होने की संभावना कम ही है, क्योंकि इससे तेहरान को रणनीतिक व आर्थिक लाभ मिलता है।

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने ईरानी सरकार से अपने देश के लिए तेल ले जाने वाले टैंकरों के सुरक्षित आवागमन की अपील की है। यानी तेहरान अब दुनियाभर की सरकारों के साथ अलग से समझौते करने की स्थिति में है। ईरान इस रणनीतिक स्थिति का उपयोग भविष्य में प्रतिबंधों में और राहत तथा अन्य कूटनीतिक रियायतें हासिल करने के लिए कर सकता है। साथ ही, जलडमरूमध्य को बंद करने

या टोल लगाने की चेतावनी ईरान के लिए सैन्य हमलों और आर्थिक दबाव के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिरोधक का काम कर सकती है। जहाज मालिक और ऊर्जा व्यापारी अतिरिक्त शुल्क का विरोध कर सकते हैं, पर इसकी लागत वैश्विक ऊर्जा व्यापार के पैमाने पर बहुत अधिक नहीं मानी जा रही है। एक बड़े ऑयल टैंकर के लिए, 20 लाख डॉलर का खर्च तेल के प्रति बैरल करीब एक डॉलर के बराबर है। ईरान की धमकियों की वजह से बीमा दरें बहुत बढ़ गई हैं; कुछ मामलों में प्रीमियम बढ़कर प्रति यात्रा 75 लाख डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात होर्मुज को फिर से खुलते हुए देखने के लिए बेताब हैं, ताकि वे अपने मुनाफे वाले तेल निर्यात को पूरी रफ्तार से फिर से शुरू कर सकें। ऐसे में, ये देश ईरान के टोल को एक आवश्यक, भले ही अस्थायी, व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इससे उन्हें ऐसी नई तेल पाइपलाइनें विकसित करने का समय मिल जाएगा, जो होर्मुज जलडमरूमध्य पर उनकी निर्भरता कम कर सकें। कतर के उप-प्रधानमंत्री पहले ही मान चुके हैं कि 'अस्थायी शुल्क' पर बातचीत की जा सकती है। होर्मुज को खुला रखने के लिए, ईरान मुआवजे की मांग करेगा। अगर वह सीधे जहाज मालिकों से भुगतान नहीं लेता है, तो संभावना है कि वह प्रतिबंधों में ढील के जरिये परोक्ष रूप से भुगतान हासिल कर लेगा। किसी भी स्थिति में, तेहरान को फायदा ही मिलेगा। और अगर सुरक्षित रास्ता ईरान की सहमति पर निर्भर करता है, तो होर्मुज पर उसका ही नियंत्रण होगा। यह स्थिति दीर्घकाल में चीन के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे उन ऊर्जा तकनीक की मांग बढ़ सकती है, जिन पर चीन का दबदबा है।

अगर दुनिया की तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा ईरान की वजह से हमेशा रुकावट के खतरे में रहता है, तो देशों के पास जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने और चीन में बने सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरी का आयात बढ़ाने की और भी बड़ी वजह होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि दुनिया एक जोखिम भरी निर्भरता को छोड़कर दूसरी निर्भरता अपना लेगी। पिछले साल रेयर-अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ मृदा धातुएं) के निर्यात पर चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने यह भी दिखाया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अहम 'चोक पॉइंट्स' कितने प्रभावशाली हथियार बन सकते हैं। इस कदम ने अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। अब ईरान ने दिखा दिया है कि होर्मुज को बंद करके दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। जिन देशों का अहम रास्तों पर नियंत्रण है, उनकी नजर से यह बात जरूर गुजरी होगी।

इतिहास में, भौगोलिक रूप से अहम और संकरे रास्तों का फायदा उठाना आम बात रही है। हालांकि, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से वैश्विक समुद्री व्यापार काफी हद तक निर्बाध और स्वतंत्र बना रहा, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा व नौवहन स्वतंत्रता की गारंटी दी थी। पर, ईरान द्वारा होर्मुज पर कब्जा करने से इस व्यवस्था में दरार आ गई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने हाल ही में पूछा, 'क्या हमें पता है कि पूर्वी एशिया की 70 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतें और 70 फीसदी व्यापार इंडोनेशिया की जलसंधियों से होकर गुजरता है?' इस टिप्पणी के बाद इंडोनेशियाई अधिकारियों ने तुरंत स्पष्ट किया कि मलक्का जलडमरूमध्य पर टोल लगाने की कोई योजना नहीं है, पर इस विचार का सामने आना यह संकेत देता है कि अमेरिकी ताकत के दम पर चलने वाला आजाद और खुला वैश्विक व्यापार अब किसी और चीज की जगह ले रहा है। मलक्का जलडमरूमध्य वही रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जिसके जरिये दुनिया के लगभग एक-तिहाई व्यापार का आवागमन होता है। भविष्य में ऐसे कई हालात बन सकते हैं। हूती बाब-अल-मंदेब पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं, रूस समुद्री इंटरनेट केबलों को निशाना बना सकता है और चीन ताइवान के आसपास जहाजों पर नियंत्रण बढ़ा सकता है। इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। इसी महीने चीन ने ताइवान के पास वाणिज्यिक जहाजों की जांच के लिए अपनी समुद्री एजेंसी के जहाज भेजे, जिसे उसने 'विशेष समुद्री यातायात कानून प्रवर्तन अभियान' बताया।

अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। इस युद्ध के जरिये ट्रंप उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। पर, विडंबना देखिए कि होर्मुज में ईरान की सफलता एक अलग तरह की होड़ शुरू कर सकती है, जिसमें हर देश पैसे और ताकत हासिल करने के लिए 'चोकपॉइंट्स' की तलाश करेगा।

आज का इतिहास

1899 ए.ई.जे. कोलिन्स ने 628 रन बनाए, यह क्रिकेट का सर्वोच्च स्कोर है।
1903 1 9 वर्षीय अमेरिकन आईडा डी अकोस्ता पावर विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी।
1905 रूसी युद्धपोत पोटेमकिन के चालक दल ने अपने दमनकारी अधिकारियों का उत्परिवर्तन शुरू किया।
1914 अमेरिका ने इथोपिया के साथ वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किये।
1927 जापान के प्रधान मंत्री तनाका गिइची ने चीन के लिए जापान की योजनाओं के बारे में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया, जिसमें से तनाका मेमोरियल, इन योजनाओं का विस्तार करने वाला एक रणनीतिक दस्तावेज था (अब माना जाता है कि यह कार्यक्षेत्र है)।
1939 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतकार एवं अभिनेता आर डी बर्मन का जन्म।
1952 ग्वाटेमाला की कांग्रेस ने डिक्री 900 पारित किया, स्थानीय किसानों को 224 एकड़ (0.9 किमी 2) से अधिक आकार की भूमि का पुनर्वितरण किया और देश के भूमि सुधार आंदोलन पर एक बड़ा प्रभाव डाला।
1957 ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी।
1967 लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया।
1977 फ्रांस ने जिबूती को स्वतंत्रता दी। जिबूती गणराज्य अफ्रीका के हॉर्न में स्थित एक देश है। यह उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम में इथियोपिया और दक्षिण में स्थित है और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से घिरा है। सीमा का शेष भाग पूर्व में लाल सागर और अदन की खाड़ी द्वारा निर्मित है।
1977 अफ़ारों और इस्सास के पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र फ्रांस से स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया और जिबूती बन गया।
1980 इतालवी विमान के तेरीहिंस सागर में दुर्घटनाग्रस्त होने से 81 लोगों की मौत।
1981 कंबोडिया ने अपना संविधान अपनाया।
1989 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 169, स्वदेशी लोगों के विषय में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, और 2007 में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया।
2007 गोर्डन ब्राउन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
2008 माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

महाराष्ट्र विधानसभा में शरिया कानून की वकालत करने वाली सना मलिक से कुछ सवाल

नीरज कुमार दुबे

अगर भारत में रहकर किसी को पाकिस्तान का कानून, शरिया आधारित व्यवस्था या कुरान के नाम पर चलने वाला शासन इतना ही पसंद है, तो सबसे पहले उसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठाना बंद कर देना चाहिए और उसी देश में जाकर बस जाना चाहिए जिसकी व्यवस्था की वह इतनी खुलकर वकालत कर रहा है। भारतीय संविधान की शपथ लेकर चुनाव जीतना, विधायक बनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचना और फिर उसी सदन में खड़े होकर पाकिस्तान जैसे देश के कानून की तारीफ करना केवल गैर जिम्मेदाराना नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक आत्मा का अपमान है। शर्मनाक बात यह है कि यह बयान किसी कट्टरपंथी संगठन के मंच से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक सना मलिक ने दिया।

हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में समान नागरिक संहिता, तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा अचानक उस समय भड़क उठी जब सना मलिक ने खुलेआम कहा कि भारत में भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए बहुविवाह और तीन तलाक का समर्थन किया। यह बयान उस समय आया जब सदन में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनके साथ हो रहे अत्याचारों पर गंभीर चर्चा चल रही थी।

पूरा मामला भाजपा विधायक देवयानी फरांदे द्वारा नियम 105 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण नोटिस से शुरू हुआ। उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं को आज भी बहुविवाह, घरेलू हिंसा और तलाक जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। देवयानी फरांदे ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में तीन मुस्लिम महिलाएं सहायता के लिए उनके पास पहुंचीं। किसी महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, तो किसी के पति ने उस पर हमला करने

की कोशिश की। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर समान नागरिक संहिता कब लागू होगी और इसके लिए क्या विशेष कार्यबल बनाया जाएगा?

लेकिन मुस्लिम महिलाओं के दर्द और उनके अधिकारों की चर्चा के बीच सना मलिक ने जिस तरह पाकिस्तान और इस्लामिक कानून का समर्थन किया, उसने पूरे सदन का माहौल गरमा दिया। सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि कुरान में जो व्यवस्था दी गई है, उसका पालन किया है और भारत को भी पाकिस्तान की तरह कुरान के नियमों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बहुविवाह केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बल्कि हर धर्म में होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि मुसलमानों में बहुविवाह का तरीका सिखाया गया है और उसका पालन होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

देखा जाये तो यह बयान केवल राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता को उजागर करता है जो भारत के संविधान से ऊपर मजहबी कानून को रखने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक महिला विधायक होकर भी सना मलिक को उन हजारों, लाखों मुस्लिम महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता जो बहुविवाह और तीन तलाक जैसी प्रथाओं की वजह से वर्षों तक प्रताड़ना झेलती रही हैं। देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जहां कई पत्नियां रखने वाले पुरुषों पर महिलाओं के शोषण, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे। इसके बावजूद बहुविवाह को जायज ठहराना आखिर किस मानसिकता का परिचायक है?

उधर, सना मलिक के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने सना मलिक के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि चर्चा का विषय तीन तलाक कानून का क्रियान्वयन है, पाकिस्तान या मजहबी परंपराएं नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह देश संविधान से चलता है, कुरान से नहीं। यहां पाकिस्तान और धार्मिक कानूनों की वकालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा और शिवसेना के विधायकों ने भी सना मलिक के बयान का जोरदार विरोध किया।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि महायुति सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लागू समान नागरिक संहिता कानून में बहुविवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन करने वालों के लिए सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि सना मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक का नाम पहले भी गंभीर विवादों में आ चुका है। वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय को उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंधों के सबूत मिलने का दावा किया गया था।

बहरहाल, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बैठे बाकी दल केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इस बयान पर चुप हैं? क्या संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधियों को खुलेआम पाकिस्तान और इस्लामिक कानून की पैरवी करने की छूट मिलनी चाहिए? यह केवल राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ सवाल है।

कैसे होगी भारतीय नागरिकों की पहचान?

सनत जैन

भारत में जन्म-मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। 1969 से यह कानून लागू है। भारत के सभी राज्यों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बाद भी उसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा है। इसके पहले 1952 के प्रथम चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की गई थी। मतदाता सूची के माध्यम से 21 वर्ष से ऊपर के नागरिकों का पंजीयन चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। यह पंजीयन चुनाव आयोग के बीएलओ घर-घर जाकर करते थे। 1969 के बाद जन्म मृत्यु पंजीयन का कानून बनाया गया था। वही नागरिकता और उम्र का प्रमाण माना जाता था। पिछले वर्ष से चुनाव आयोग ने अपने ही बनाये गये मतदाता कार्ड को अमान्य बता दिया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए नागरिकता के लिए जो पहचान के दस्तावेज जरूरी बताए थे, उसे भी सुप्रीम कोर्ट, विदेश मंत्रालय और सरकार के विभिन्न निर्णय में नकार दिया गया है। कोई भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत के नागरिक हैं, इसको साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज है, इसका कोई उल्लेख ना तो चुनाव आयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने नागरिकता के प्रमाण स्वरूप कौन से दस्तावेज होंगे, इसका फैसला नहीं किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग की मतदाता सूची और मतदाता प्रमाण को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना। आधार और पासपोर्ट भी नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर कौन सा प्रमाण पत्र है, जिसे भारतीय नागरिक होने का प्रमाण माना जाए। इसको भारत सरकार भी नहीं बता पा रही है। ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान एवं अन्य देशों से आकर भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। विदेश से आने वालों को केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता का प्रमाण पत्र देता है। भारत में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जो आपके भारत में जन्म और नागरिक होने का प्रमाण माना जाए।

75 सालों बाद यह स्थिति पहली बार चुनाव आयोग के कारण देखने को मिल रही है। अब सब जगह से एक ही आवाज सुनने को मिल रही है, हम कैसे प्रमाणित करें, हम भारतीय नागरिक हैं। अब तो यह भी कहा जाने लगा है, भारतीय नागरिक वही होगा, जो हिंदू हो, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो। उसे ही भारत के नागरिक होने का प्रमाण मान लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने जब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सारे देश में अनिवार्य किया था। इसका एक ही उद्देश्य था जन्म के साथ ही भारतीय तथा उम्र नागरिकता प्रमाणित हो जाए। आधार कार्ड को भी जब अनिवार्य किया गया था, हर नागरिक और बच्चों का इसमें पंजीयन कराना था। इसमें आंखों की पुतलियां और हाथ के छापे भी लगवाए गए थे। ताकि भारतीय नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कराया जा सके। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने आधार के दस्तावेजों को नकार दिया है। भारत सरकार यह भी नहीं बता रही है, भारतीय नागरिक होने का ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है, जिसे भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार किया जा सके। यह स्थिति देश में पहली बार देखने को मिल रही है। लोग अभी यह कहने लगे हैं, विदेश से आकर भारतीय नागरिकता लेना और प्रमाणित करना आसान है, लेकिन आपकी कई पीढ़ियां जिनका जन्म भारत में हुआ है, शिक्षा-दीक्षा, संपत्ति सब भारत में है, इसके बाद भी उसके पास भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जिस तरह से इस मामले में अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पासपोर्ट को लेकर कहा जाता है, भारत में मात्र दो फ़ीसदी लोगों के पासपोर्ट हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है, यह नागरिकता होने का प्रमाण पत्र नहीं है। नागरिकता के मामले में भारत सरकार और गृह मंत्रालय की चुप्पी आश्चर्यजनक है। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जिसने अपने फैसले में यह नहीं बताया भारतीय नागरिक होने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र स्वीकार होगा। वर्तमान में नागरिकता को लेकर चुनाव आयोग ने रायता फैलाया है। उसके बाद से अब यह बहुत बड़ा विवादित मामला बन गया है। इसका पटाक्षेप किस तरह से होगा, इसके लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

चढ़ावे की चोरी: लीपापोती होगी या होगा राजफाश

राधा रमण

भले ही अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच चुकी है, लेकिन इस मामले की अब तक कोई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं कराई गयी है। बिना एफआईआर के इस रिपोर्ट का मतलब क्या है ? विपक्ष के लगातार हमलों, आस्थावान लोगों की चिन्ता, हिन्दू संगठनों की मांग और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के आग्रह पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। जांच दल के अन्य सदस्यों में लखनऊ रेज के आईजी किरण शिवकुमार और उत्तरप्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार शामिल थे। एसआईटी ने छह दिन अयोध्या में रुक कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्र और व्यवस्थापक गोपाल राव समेत सेवादार रामशंकर यादव उर्फ टिंकू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, अवनीश, सोमेश आनन्द समेत करीब 60 लोगों से पूछताछ के बाद रिपोर्ट सौंपी है। विशेष जांच दल ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी पूछताछ की है और बैंक स्टेटमेंट तथा वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की है।

बताया जाता है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी को क्लीनचिट नहीं दी है। साथ ही विस्तृत जांच के लिए और समय की मांग की है। एसआईटी को अब तक की जांच में कई गड़बड़ियों के सुबूत मिले हैं। जांच में सीसीटीवी में छेड़छाड़ के भी सुबूत मिले हैं। दान की राशि के रिकॉर्ड से भी एसआईटी संतुष्ट नहीं है। अभी तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे न सिर्फ नकदी बल्कि दान किये गए सोना-चांदी और हीरे-जवाहरात की भी हेराफेरी की आशंका है। इसलिए विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट का पुनर्गठन करने, मंदिर के प्रबंधन को व्यवस्थित करने, चढ़ावा और जेवरात की निगरानी करने, जवाबदेही तय करने और किसी प्रशासनिक अधिकारी की बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति करने की भी सिफारिश की है।

सात जून को अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पाण्डेय ने राममंदिर के चढ़ावे में 7.50 करोड़ की हेराफेरी का

आरोप लगाया था, तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लपक लिया और सरकार से न्यायिक जांच की मांग की। तब जाकर लोगों को मामले की गंभीरता का पता चला। फिर क्या था, बजरंग दल के अध्यक्ष और राममंदिर प्रबंध समिति से दरकिनार किये गए पूर्व सांसद विनय कटियार, धर्मसेना के प्रमुख संतोष दुबे, हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा और कुछ साधु संतों ने अखिलेश के आरोपों को हवा दे दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जमीन खरीद में गड़बड़झाला को लेकर थाने में शिकायत लेकर पहुंच गए। शुरुआत में तो उत्तरप्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई नेता प्रदेश की मस्जिदों के चढ़ावे में हेराफेरी का आरोप लेकर काउंटर करने मैदान में उतरे लेकिन आखिरकार जीत रामभक्तों की ही हुई। यह आज की राजनीति का नया चलन है। यहां सवाल के बदले सवाल किये जाते हैं। दबाव में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष जांच दल का गठन करना पड़ा। लेकिन एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाने से शक गहरा रहा है। कायदे से रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है।

बड़ा सवाल यह कि क्या केंद्र के कहने पर उत्तरप्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था ? यदि यह सही है तो प्रधानमंत्री इस मसले पर अभी तक चुप क्यों हैं ? गृहमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उत्तरप्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राम आम आदमी के रोम-रोम में बसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राममंदिर बनवाने के नाम पर ही देश-प्रदेश में सत्ता के शिखर पर पहुंची है। यदि राम के चढ़ावे की चोरी होती रही और गुनहगार बेखौफ घूमते रहे तो निश्चित रूप से दोषियों को बचाने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था कि जैसे प्रभु श्रीराम के मंदिर के लिए 500 साल प्रतीक्षा किया, वैसे चढ़ावा चोरी की जांच के लिए 15 दिन तक इंतजार करें, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बेशक, लोगों को मुख्यमंत्री के भरोसे का सम्मान करना चाहिए।

सवाल यह भी है कि क्या ट्रस्ट में शामिल लोगों को पद से हटा देने भर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ? अभी तक बिना एफआईआर कराये कुछ लोगों से दो करोड़ से अधिक रुपये की बरामदगी हो चुकी है। रामशंकर यादव के घर से कुछ सोना भी बरामद हुआ है। ऐसे में जाहिर है कि मामला 7.50 करोड़ की हेराफेरी का ही नहीं है। उससे ज्यादा का है। चोरों का गिरोह कब से यह काम कर रहा था, अभी तो इसका भी पता नहीं चला है। अयोध्या में सेवादारों की नियुक्ति कौन करता है ? इसके मानक क्या हैं ? बहाली से पहले उनकी जांच-पड़ताल होती भी है या नहीं। रामशंकर पहले ऑटो चलाया करता था। फिर चंपत राय की कार चलाने लगा। अब राममंदिर की सेवा में आने के बाद उसके 70 कमरों का होटल और अयोध्या ङ्क लखनऊ में आलीशान मकान कहां से बन गए। अनुकल्प मिश्र ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्र का बेटा है। पहले क्या करता था। राममंदिर में सेवा के दौरान उसने कहां से इतनी कमाई कर ली कि डेढ़ करोड़ रुपये की जमीन खरीद ली और बंगला बना लिया। लवकुश अनुकल्प का साला लगता है। उसके ठिकाने से घर के घूरे में रखे 12 लाख रुपये नकद मिले हैं। अयोध्या में 40 लाख कीमत की जमीन भी है। सवाल यह भी है कि ट्रस्टियों के मनोनयन से पहले क्या सरकार ने उनकी माली हालत की जांच कराई थी ? ट्रस्ट में आते ही वे मालामाल कैसे हो गए ?

उत्तरप्रदेश कैडर के 1967 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अवकाशप्राप्त अधिकारी नृपेन्द्र मिश्र पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव थे। अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं। वे राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि मामला चढ़ावा चोरी का नहीं, डकैती का है। तो क्या नृपेन्द्र मिश्र पवन पाण्डेय और अखिलेश यादव के आरोपों का इंतजार कर रहे थे? अब तक चुप क्यों थे?

जंग की पाकी धमकी के पीछे किसका हाथ?

राजेश बादल

पाकिस्तान फिर जंग पर आमादा है।अब उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकाया है। वे कहते हैं कि भारत ने अगर सिंधु जल संधि तोड़ी तो फिर युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहे। भारत ने रक्षामंत्री की धमकी को खारिज कर दिया है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी युद्धोन्माद को गीदड़ भभकी मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। इन दिनों पाकिस्तान जबरदस्त आंतरिक वित्तीय संकट से जूझ रहा है।वहाँ की अवाम का अगर बस चले तो हुक्मरानों को सड़कों पर सजा दे। पर,उसके ऊपर फौजी तलवार लटकी हुई है। फील्डमार्शल आसिम मुनीर पहले ही अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमेरिकी सम्राट इससे प्रसन्न हैं और उसे वरदान देना चाहते हैं।

सूत्रों के मुताबिक इस बार फिर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर मांगा है। साठ के दशक में भी वह ऐसा करता रहा है।उसने कश्मीर पाने के लिए मध्य पूर्व के मुस्लिम मुल्कों के हाथ जोड़े,तत्कालीन सोवियत संघ से गिड़गिड़ाया,चीन से गुहार की और अमेरिका के चरणों में लोट लगाई। लेकिन,कश्मीर उसे नहीं मिला। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आते हैं इसलिए जंग के मुहाने पर दोनों देशों को ले जाकर वे भारत पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। हालिया बयान में ख्वाजा साहब एक टेलीविजन चैनल एआरवाई पर कहते हैं कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है।

अगर हिन्दुस्तान सिंधु नदी की धारा रोकने का प्रयास करेगा तो हम उसके लिए युद्ध करने से भी नहीं हिचकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज के सुप्रीम कमांडर (असल में तो पाकिस्तान के सुप्रीमो भी वही हैं) आसिम मुनीर ने भी जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं। उधर से आ रही खबरों पर भरोसा करें तो नियंत्रण रेखा इन दिनों दिन रात पाकिस्तानी सैनिकों के बूटों की आवाज़ से गूंज रही है। करीब 50 स्थानों पर ड्रोन आक्रमण को रोकने वाली प्रणालियां तैनात कर दी गई हैं। बताने की आवश्यकता नहीं कि इन प्रणालियों को अमेरिका और तुर्किए ने मुहैया कराया है।

ध्यान देने की बात यह है कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ड्रोन-तंत्र निर्यात कर रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बाकायदा रक्षा समझौता हो चुका है। यानी भारतीय पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर एक साथ आक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। पाक ने अफगानिस्तान सीमा पर तैनात कुछ बटालियनें कश्मीर सीमा पर लगाई हैं। तात्पर्य यह कि इस बार वह अपनी योजना को बेहद पेशेवर ढंग से अंजाम दे रहा है।

पहली बार बांग्लादेश भारत के उग्र विरोध पर उतरा है। वहां की सरकार पर भी अमेरिका का हाथ है। इसलिए तीन तरफ से हिन्दुस्तानी सीमा असुरक्षित दिखाई दे रही है। चीन एक चतुर और चालाक व्यापारी है। वह भले ही उत्तरी सीमा से आक्रमण नहीं करे,मगर भारत को उस ओर से निश्चिंत भी नहीं रहने देगा। वह कुछ न कुछ हरकतों को अंजाम देता रहेगा। चीन की विदेश नीति का मूल तत्व भी यही है कि उसके दो बड़े पड़ोसी रूस और भारत इतने ताकतवर न बनें कि उसके लिए मुश्किल कड़ी कर सकें। इसलिए वह नेपाल और पाकिस्तान के माध्यम से भारत के सामने कठिनाई पेश करता रहा है।

उधर,अमेरिका के दोहरे रवैए के कारण भारत उस पर भरोसा तो नहीं कर सकता,लेकिन रूस के साथ स्वाभाविक मैत्री चीन,अमेरिका और पाकिस्तान पर हरदम अपरोक्ष दबाव बनाए रखेगी। इसलिए अमेरिकी दामन से हमेशा के लिए दूर रहकर रूसी के साथ चलने में ही भलाई है। रूस के साथ रिश्तों में ठंडापन भारत के भविष्य में नहीं है।

यह तो पाकिस्तान भी जानता है कि वह लाख कोशिशें कर ले,कश्मीर उसकी पहुंच से दूर ही रहेगा। फिर वह इस बार भारतीय घेराबंदी क्यों कर रहा है? दरअसल उसका इरादा एक तीर से कई निशाने लगाने का है। अव्वल तो अमेरिका से धन वसूलना है ,जो वह ईरान के साथ मध्यस्थता के बदले वसूलना चाह रहा है। हमेशा की तरह इस धन को दो जगह लगाया जाएगा। एक तो भारत के खिलाफ हथियार और रक्षा उपकरणों की खरीद करने के लिए और दूसरा अपनी सेना के आला अफसरों की जेब भरने के लिए।

बता दूं कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी ड्यूटी के अलावा सभी तरह के कारोबार में संलग्न हैं। वे सीमेंट बनाते हैं,बेकरी चलाते हैं, पेट्रोल पंप संचालित करते हैं, रियल स्टेट में हैं,भू माफिया हैं,विशाल इमारतें बनाते हैं और गैस उत्पादन जैसे अनेक धंधे करते हैं।

एक अनुमान के मुताबिक पाक सेना क़रीब पांच लाख करोड़ का धंधा करती है। विपक्ष के जोर देने पर सरकार ने वहां की असेंबली में दस्तावेज रखे थे। उनके अनुसार फौज लगभग डेढ़ लाख करोड़ का व्यापार करती है। इसके अतिरिक्त कई देशों में उसके जनरल धंधा करते हैं। पाकिस्तान का तीसरा मकसद अमेरिका को भारत से दूर रखना है। इसमें वह कामयाब हो रहा है। यह अलग बात है कि चौधरी ट्रंप पर भारत का कोई भी नागरिक भरोसा नहीं करेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे उग्र और हिंसक आंदोलन को दबाना और उससे विश्व का ध्यान हटाना भी वहां की हुकूमत का उद्देश्य है।

इसके अलावा मंहगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को एक बार फिर धर्म के नाम पर, कश्मीर के नाम पर और भारत से नफरत फैलाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास भी वहां के सत्तारूढ़ नेताओं का प्रयास है। भारत के नजरिए से देखें तो लगता है कि अमेरिका,पाकिस्तान और बांग्लादेश का त्रिकोण आने वाले दिनों में संकट खड़ा कर सकता है। जल संधि तो एक बहाना है। इसलिए भारतीय विदेश और रक्षा नीति नियंताओं के लिए कूटनीतिक और आक्रामक रवैया अपनाना समय की मांग है। भारत के लिए ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को बहाल करना भी जरूरी है। ध्यान रखना होगा कि विदेश नीति में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ जाती है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ अपने संबंध एक बार फिर समीक्षा की मांग करते हैं।

निर्वाचित सदस्यों के दलबदल का मतलब मतदाताओं को धोखा देना है!

विश्वनाथ सचदेव

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना फिर टूट गई है। पहले चालीस विधायकों ने बगावत की थी और अब उद्धव के छह सांसद पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक को छोड़कर बाकी पांच ने यह कदम उठाने का कारण बताते हुए मूल शिवसेना की नीति-रीति का हवाला दिया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस का साथ दिया है, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब दलबदलू राजनीति का बदरंग चेहरा सामने आया है। देश में 'आयारामों-गयारामों' की एक लंबी सूची है। दल बदलुओं की यह कथा लगभग छह दशक पहले शुरू हुई थी। कहानी अब भी जारी है। तब भी दल बदल के पीछे कारण कोई सिद्धांत या नीति नहीं थी और अब भी दिखाई यही दे रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक लाभ ही इस जनतंत्र- विरोधी कार्रवाई का मूल कारण है। हमारे संविधान-निर्माताओं ने शायद ही कभी सोचा होगा कि हमारे राजनेता इतना गिर जाएंगे, पर आज यह स्थिति एक खुली किताब की तरह सामने है। न दल बदलने वालों को शर्म आती है और न दलबदल करवाने वालों को। मजबूत विपक्ष जनतंत्र के औचित्य और सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त है। मज़बूत सरकार की तरह ही एक सुदृढ़ विपक्ष भी चाहिए होता है। कमजोर विपक्ष का मतलब होता है एक ऐसी सरकार को अवसर और छूट देना जो कभी भी तानाशाही का रास्ता अपना सकती है। हाल ही के दिनों में हुई दलबदल की घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अजनतांत्रिक ताकतें लगातार सक्रिय हो रही हैं। कुछ अर्सा पहले हमने पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसदों को दल-बदल करके भाजपा की शरण में जाते देखा था। फिर हमने देखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की

पराजय के बाद उसके विधायकों और सांसदों ने दलबदल करना जरूरी समझ लिया। नवीनतम उदाहरण महाराष्ट्र में टूटी हुई उद्धव ठाकरे की पार्टी को और तोड़ने का है। जैसी स्थितियां बना रही हैं, उनसे इस आशय के संकेत भी मिल रहे हैं कि टूटने-बिखरने का खतरा शरद पवार की एनसीपी को भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री इस आशय के संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव की सोशलिस्ट पार्टी भी डोरे डाले जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत भी घटा दी गई है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो संसद में विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर थी। कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें प्राप्त हुई थीं। विपक्ष को मिली कुल 125 सीटों में सबसे बड़ा दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसे मात्र 16 सीटें मिली थीं। भारतीय जनसंघ के हिस्से में सिर्फ तीन सीटें आई थीं। तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा था, चूंकि विपक्ष सदन में कमज़ोर है, इसलिए उन्हें ही विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी। अर्थात सरकार के काम-काज पर नजर रखनी होगी। आयाराम-गयाराम वाली स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि दलबदल कानून को मज़बूत बनाया जाए। इसके लिए पहली जरूरत तो यह है कि दलबदल करने वालों को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने की शर्त हो। निर्वाचित सदस्यों के दलबदल का मतलब मतदाताओं को धोखा देना ही है। नैतिकता का तकाज़ा है कि वे दल बदलना चाहते हैं तो पद से त्यागपत्र दें।

अपने आहार पर करें फोकस आंखें रहेंगी अच्छी

सूरजमुखी के बीज और नट्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के साथ-साथ जब अन्य पोषक तत्वों का सेवन किया जाता है तो इससे उम्र के होने वाली आंखों की कमजोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है।

आंखें यकीनन व्यक्ति के शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। छोटी सी आंखों की मदद से आप इतने बड़े संसार को देख पाते हैं। लेकिन आज के समय में जब लोग अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं तो उसके कारण आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि बेहद कम उम्र में ही लोगों की आंखों पर चश्मा लग जाता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपनी आंखों की रोशनी को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने आहार पर भी फोकस करें। तो चलिए आज हम आपको उन आहार के बारे में बता रहे हैं जो आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा है-

कच्ची लाल शिमला मिर्च

शिमलामिर्च में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। यह आपकी आंखों की रक्तवाहिकाओं के लिए अच्छा है। वहीं लाल शिमलामिर्च से आपको विटामिन ए और विटामिन ई भी प्राप्त होता है, जो आपकी आंखों को तंदरूस्त बनाने में मदद करता है।

सूरजमुखी के बीज और नट्स

सूरजमुखी के बीज और नट्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के साथ-साथ जब अन्य पोषक तत्वों का सेवन किया जाता है तो इससे उम्र के होने वाली आंखों की कमजोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मोतियाबिंद को रोकने में भी मददगार है। वैसे आप नट्स के साथ-साथ हेजलनट्स, मूंगफली और पीनटबटर का सेवन करके भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पा सकते हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियां

केल, पालक व अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी और ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इतना ही नहीं, इनमें कैरोटिनॉयड्स ल्यूटिन और जैक्सैंथिन भी होता है। साथ ही इनमें पाया जाने वाला विटामिन ए लंबे समय में आंखों की बीमारियों से भी व्यक्ति की रक्षा करता है।

सैल्मन

आपकी आंखों के रेटिना को सही काम करने के लिए दो प्रकार के ओमेगा-3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है- डीएचए और ईपीए। आप फैटी फिश, जैसे सैल्मन, ट्यूना और ट्राउट व अन्य कई सी-फूड में इसे पा सकते हैं। वहीं इन फैटी एसिड के कम होने पर लोगों को डाई आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है।

शकरकंद में बीटा-कैरोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो वास्तव में विटामिन ए का ही एक रूप है। यह आपके नाइट विजन को बेहतर बनाता है। वहीं एक शकरकंद से आपको दैनिक आवश्यकता की आधे से ज्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होती है, वहीं इसमें कुछ मात्रा में विटामिन ई भी पाया जाता है। वैसे शकरकंद के अलावा गाजर, कैंटालूप, आम और खुबानी में भी बीटा-कैरोटीन उच्च मात्रा में होता है।

लंच या डिनर से आधा घंटा पहले खाएं सलाद

सलाद लगभग हर जगह खाई जाती है। हां इसके रूप अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं उबालकर तो कहीं भूनकर. हमारे यहां सलाद को ताजा सब्जियों जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर और कच्ची प्याज आदि से तैयार किया जाता है। क्योंकि यह सलाद कच्चा होता है और प्याज के अलावा ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें अलग से खाया जा सकता है। इसलिए हमारे यहां भोजन के साथ सलाद खाने को वर्जित माना गया है। ये और बात है कि यंग जनरेशन को अपनी ही परंपराओं को बारे में जरा कम पता है!

सलाद खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह बात हम सभी जानते हैं। इसलिए फलों से लेकर सब्जियों और स्प्राउट्स की सलाद हमारे यहां खूब खाई जाती है। जबकि कुछ लोग या कहिए कि सलाद के शौकीन ज्यादातर लोग अपने शरीर को सलाद का पूरा पोषण नहीं दे पाते। क्योंकि उन्हें सलाद खाने का सही तरीका ही नहीं पता है.

सलाद खाने का सही समय

सलाद हमेशा ही भोजन से पहले खानी चाहिए। जबकि लगभग 90 प्रतिशत लोग सलाद का सेवन खाने के साथ करते हैं। इससे उनके शरीर को सलाद का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बल्कि कई बार डायजेशन से संबंधित समस्याएं हो जाती है।

इतनी देर पहले खाएं

जब आपको भूख लगी हो या आपने जो भी अपने लंच और डिनर का समय तय कर रखा है, उससे कम से कम आधा घंटा पहले सलाद खा लें। इसके बाद लंच या डिनर लें। इससे आपके शरीर को पूरा पोषण मिलेगा और ओवर इटिंग से छुटकारा भी।

वेट रहता है कंट्रोल

सलाद अगर सही तरीके से खाई जाए तो इससे वेट को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। यह हमारे पाचनतंत्र को सही रखती है और पेट साफ करने में मदद करती है। यह शरीर में एक्सट्रा फैट जमा होने से रोकती है और हमें ओवर ईटिंग से भी बचाती है। जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है।

सलाद के तरीके

आमतौर पर सलाद दो तरीके से बनाई जाती है। पहला तरीका का कच्चा सलाद, जिसमें आप फल और सब्जियों को काटकर मिक्स करते हैं और मसाला छिड़ककर सैलेड तैयार कर लेते हैं। जबकि दूसरा तरीका है वॉइल करके सैलेड तैयार करना। इसमें सब्जियों को उबालकर उनका पानी अलग करके सलाद तैयार किया जाता है। लेकिन आप कोई-सी भी सलाद खाए आपको इसे फुल मील के साथ नहीं खाना है।

क्यों ना खाएं भोजन संग सलाद

सलाद चाहे जैसे भी बनाई गई हो। अगर यह फलों या सब्जियों से तैयार की गई है तो आमतौर पर इनकी प्रकृति ठंडी होती है (हम यहां किसी रेसिपी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर तरह के भोजन को एक साथ डिस्क्राइब या कंपेयर नहीं किया जा सकता) जबकि पका हुआ भोजन गर्म होता है। ऐसे में ठंडे गर्म का संगम, सिर्फ शरीर ही नहीं दांतों को भी हानि पहुंचाता है।

पाचन में अधिक समय

सलाद तापमान में ठंडी होती है और भोजन तापमान में गर्म होता है। जब कच्चा और पका हुआ भोजन एक साथ खाया जाता है तो इससे हमारे पाचनतंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है। क्योंकि इसे पचाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। साथ ही ऐसा भोजन डायजेस्ट करने में अधिक समय भी लगता है, जिससे कई बार डायजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है।

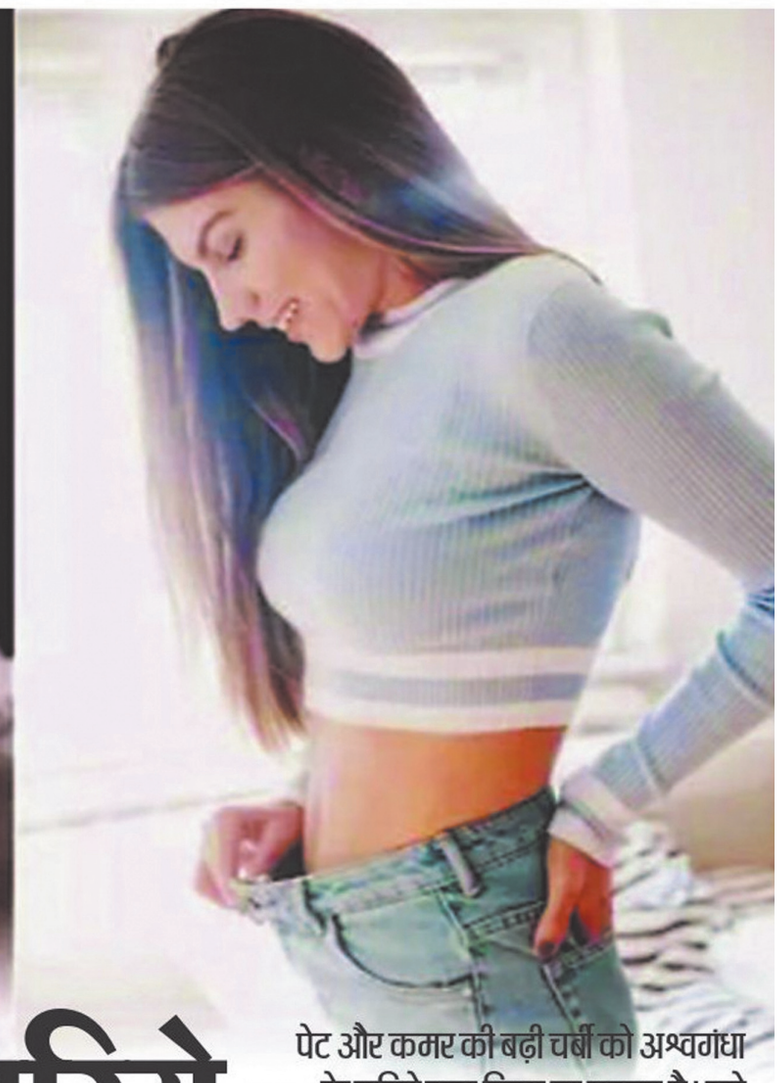

अश्वगंधा के जरिये कम किया जा सकता है मोटापा

पेट और कमर की बढ़ी चर्बी को अश्वगंधा के जरिये कम किया जा सकता है। इसे रोज दूध के साथ पीने से जल्द ही लाभ मिलेगा। इसे पावडर के रूप में या फिर कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है।

दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा मिला कर पीने से दूर हो जाता है मोटापा, जानें कैसे करता है कामजड़ी बूटियों का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इनमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाये जाते हैं जो बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं और शरीर को निरोगी बनाए रखती हैं। अश्वगंधा एक ऐसी ही जड़ी बूटी है जो न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करती है बल्कि वजन घटाने में भी बहुत प्रभावी होती है। अश्वगंधा का उपयोग न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि यूनानी, सिद्ध, अफ्रीकन और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी किया जाता है। अश्वगंधा अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन, यौन समस्याएं, कमजोरी और अर्थराइटिस जैसे रोगों को इलाज में उपयोगी है। इसके अलावा अतिरिक्त फैट को बर्न करने में भी अश्वगंधा बहुत फायदेमंद हैं। आइये जानते हैं वजन घटाने में अश्वगंधा के फायदे। तो अगर आप नेचुरल तरीके से वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करना चाहिये.

अश्वगंधा का सेवन कैसे करें

वैसे आपको बाजार में अश्वगंधा कैप्सूल के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अश्वगंधा पाउडर अधिक फायदेमंद होता है। इसे लेने का तरीका बेहद आसान है। एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच अश्वगंधा पावडर और शहद मिलाकर रोजाना सेवन करने से मेटाबोलिज्म और पाचन बेहतर होता है। आप चाहें तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिये इसमें इलायची पावडर मिक्स कर सकते हैं। इससे मेटाबॉलिजिम तो बढ़ेगा ही साथ में पाचन भी मजबूत रहेगा।

सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए

अश्वगंधा हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है, जिससे शरीर में खाना अच्छी तरह से हजम होता है और मेटाबोलिज्म बढ़ता है। यह फैट को जल्दी जल्दी बर्न करने में मदद करती है। अगर आप घंटो जिम में एक्सरसाइज करते हैं और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से मोटापा कम नहीं हो पा रहा है तो आज से ही अश्वगंधा लेना शुरू कर दें। इससे कम समय में ही मोटापा कम हो जाता है।

स्ट्रेस दूर कर घटाए मोटापा

स्ट्रेस या कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से मोटापा भी बहुत तेजी से बढ़ता है। नियमित रूप से अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से इस हार्मोन को कम करने में मदद मिलती है। कोर्टिसोल बढ़ने की वजह से इंसान को बार बार भूख भी लगती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। तनाव से मुक्ति मिलते ही पेट की चर्बी घटने लगती है।

मांसपेशियां बनाने में

अश्वगंधा में ऐसे कई तत्व पाये जाते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मसल्स मास बढ़ने से शरीर पर चर्बी नहीं जमती और वजन नियंत्रित रहता है।

इम्यूनिटी बढ़ा कर घटाए मोटापा

अश्वगंधा में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम करता है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है जिसके कारण शरीर पर अतिरिक्त वसा जमा नहीं होती है और वजन नियंत्रित रहता है। यही नहीं अगर शरीर में सूजन है तो यह उसको भी कम करती है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।

वर्कआउट के लिये बढ़ाती है एनर्जी लेवल

अश्वगंधा एड्रिनल ग्लैंड और कोर्टिसोल लेवल को नियंत्रित करता है जिससे तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। इससे शरीर की एनर्जी बढ़ती है और थकान दूर होती है। ऐसे में जब आप भारी वर्कआउट करते हैं तो अश्वगंधा शरीर को एनर्जी से भर देता है। यही नहीं अश्वगंधा आयरन से भरपूर होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है

अच्छी नींद लाए

रात को अगर आप अधूरी नींद लेते हैं तो न तो आपको मोटापा घटेगा और ऊपर से शरीर को तनाव, उच्च रक्त चाप जैसी बीमारियां और घेर लेंगी। रात में सोते वक्त आपका शरीर हारमोन्स को संतुलित करता है और स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ने से रोकता है। इससे मोटापा कम करने में मदद मिलेगी।

ध्यान रखें अश्वगंधा का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अत्यधिक सेवन से न सिर्फ उल्टियां हो सकती हैं बल्कि पेट गड़बड़ हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे न खाएं। नींद न आने पर अश्वगंधा का इस्तेमाल कुछ हद तक सही है, लेकिन नींद बुलाने के लिए इसका नियमित सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस प्रकार औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण अश्वगंधा बीमारियों को दूर करने के अलावा वजन कम करने में भी बहुत फायदेमंद है। नियमित एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से जल्दी की फर्क नजर आता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

शिवराज के बेटे पर बयान राहुल को पड़ा भारी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आठ साल पुराने मानहानि मामले में बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह पर बयान देने के लिए राहुल गांधी ने खेद व्यक्त किया है. राहुल की तरफ से इस संबंध में कोर्ट में लिखित रूप से आवेदन दिया गया है. यह पूरा मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि के परिवाद से जुड़ा हुआ है. अब इसे केस में हाईकोर्ट की जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ गुरुवार को अहम सुनवाई करने जा रही है. मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले राहुल के वकील ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसे लेकर केवल एक गलतफहमी हुई थी.राहुल की इस सफाई और लिखित आवेदन पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता कार्तिकेय चौहान से जवाब लिखित प्रतिक्रिया देने को कहा है।

राजा भैया के पिता समेत 13 समर्थक हाउस अरेस्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से एक खबर सामने आ रही है. मुहर्रम के मौके पर कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बाहुबली कुंडा विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 13 समर्थकों को हाउस अरेस्ट कर दिया है. कुंडा के उप जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, राजा उदय प्रताप सिंह के साथ जितेंद्र यादव, आनंदपाल, रमाशंकर मिश्र, भवानी विश्वकर्मा, रवि सिंह, हनुमान प्रसाद पांडेय, केसरी नंदन पांडेय, जमुना प्रसाद मौर्य, निर्भय सिंह, गया प्रसाद प्रजापति, मोहनलाल और जुगनू विश्वकर्मा को 25 जून सुबह 5 बजे से 26 जून रात 9 बजे तक अपने आवासीय परिसर में ही रहने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि शेखपुर आशिक गांव में हर साल मुहर्रम के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती और तनाव की स्थिति के पीछे एक दशक से अधिक पुरानी घटना है।

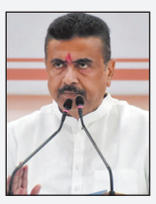

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर शुरू करेगा भारत

नई दिल्ली। बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को ढाका में अपना पदभार संभालने के साथ ही, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा की है.भारतीय जनता पार्टी के 76 वर्षीय नेता दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने क्रेडेंशियल सौंपे और औपचारिक रूप से अपना राजनयिक काम शुरू किया. त्रिवेदी, जिन्हें 27 अप्रैल को बांग्लादेश में दूत नियुक्त किया गया था, वे इस पद पर काम करने वाले पहले राजनेता हैं.वहीं, बंगभवन राष्ट्रपति महल के एक प्रवक्ता ने कहा, भारत के नए हाई कमिश्नर ने राष्ट्रपति को अपने क्रेडेंशियल सौंपे हैं और ढाका में अपना राजनयिक काम शुरू किया है.प्रवक्ता ने बताया कि अपने राजनयिक कागजात सौंपने से पहले प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने त्रिवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. समारोह के तुरंत बाद, त्रिवेदी राजधानी में भारतीय वीजा केंद्र में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए, जहां उन्होंने ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा की.

इबोला के खतरे के बीच भारत अलर्ट

नई दिल्ली। भारत में अभी इबोला वायरस का कोई केस नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में अलर्ट है. भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी को और मजबूत कर दिया है. इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मिलकर ,ढ्ढक्र स्ङ्कढ्ढष्ठ॥ 2.0 नाम का नया डिजिटल हेल्थ डिक्लेरेशन पोर्टल लॉन्च किया है. इसके जरिए भारत आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहले से जुटा ली जाएगी ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके.विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में फैले इबोला वायरस को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. इसके बाद भारत ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में हेल्थ सर्विलांस को मजबूत किया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी वायरस का खतरा कम करने के लिए विदेशों से आने वालों की समय पर निगरानी जरूरी है. इससे समय रहते संक्रमण की रोकथाम हो सकती है।

दिल्ली मेडिकल खरीद मामले की ईडी जांच शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए करीब 600 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण खरीद में कथित घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने भी शुरू कर दी है. ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. श्वष्ठ की दिल्ली जोन-2 टीम ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज , दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी और डीजीएचएस द्वारा की गई सभी मेडिकल खरीद से जुड़े दस्तावेज मांगे है. ईडी की जांच के दायरे में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन जैसे महंगे मेडिकल उपकरण शामिल हैं. इसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट , बेड शीट, लिनेन सामान, सर्जिकल आइटम, ड्रेसिंग, स्यूचर, कैनुला, ग्लव्स और दवाइयों जैसी आवश्यक सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया को भी खंगाला जा रहा है.टेंडर प्रक्रिया पर श्वष्ठ की नजर जांच एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, ठेके देने के नियम, सामान की सप्लाई, जांच, मंजूरी और पेमेंट रिलीज से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स मांगे हैं।

ड्रग माफियाओं पर बड़ा प्रहार, अमित शाह ने जारी किया नया रोडमैप

छह हजार करोड़ के नशीले पदार्थ किए गए नष्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर देश के युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए सरकार के अटूट संकल्प पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक सुरक्षित समाज के निर्माण और प्रभावित व्यक्तियों को उचित देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रशासन नशे की लत से प्रभावित लोगों की देखभाल करते हुए तस्करी नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

उन्होंने लिखा, नशीली दवाओं के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं के खिलाफ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नशीले पदार्थों के गिरोहों का निर्मम उन्मूलन करके और प्रभावित व्यक्तियों को उचित देखभाल और सहानुभूति प्रदान करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। पोस्ट में लिखा था कि यह दिन हमारी युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे। #नशामुक्तभारत।

देश में नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ केंद्र सरकार अपनी कार्रवाई को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की की। इस दौरान उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया। इससे देश को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए अगले तीन वर्षों का रोडमैप तय किया गया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के

दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियानों की समीक्षा करना और उन्हें और मजबूत बनाना है। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सरकार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को और प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

अमित शाह ने कहा सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

- अगले एक वर्ष में किसी भी सूचकांक (इंडिकेटर) में गिरावट नहीं आनी चाहिए।
- हर मानक में उल्लेखनीय सुधार होना चाहिए और यह अगले वार्षिक रिपोर्ट में भी दिखाई देना चाहिए।
- नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई खुफिया जानकारी (इंटेलिजेंस) आधारित होनी चाहिए।
- ड्रग तस्करी से निपटने के लिए नेटवर्क-केंद्रित (नेटवर्क-सेंट्रिक) रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।
- नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई में कठोर और निर्दयी रवैया अपनाना जरूरी है।

केवल सख्त और समन्वित कार्रवाई के जरिए ही इस चुनौती पर विजय हासिल की जा सकती है।

नए विजन डॉक्यूमेंट में क्या खास?

- नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 में नशीले पदार्थों की मांग कम करने, तस्करी की सप्लाई चेन तोड़ने और नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह दस्तावेज आने वाले वर्षों में ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय रणनीति का आधार बनेगा।
- विजन डॉक्यूमेंट में नई चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी शामिल की गई है। इनमें सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता इस्तेमाल और डार्कनेट के जरिए हो रही ड्रग तस्करी प्रमुख हैं। इसके अलावा, नशे से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता अभियान, इलाज की सुविधाएं और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

गृह मंत्री ने इस दौरान ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत देशभर में जब्त किए गए लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया। इन नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपये बताई गई है। सरकार का मानना है कि यह अभियान ड्रग तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाएगा।

वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं उन विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना करता हूं जो इस अभियान को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा-मुक्त भारत बनाने की दिशा में सार्थक योगदान दे रहे हैं। आइए, हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएं, नशा छोड़ने की प्रक्रिया से गुजर रहे लोगों का समर्थन करें और अपने युवाओं को नशे के बजाय उम्मीद, सेहत और जीवन के मकसद को चुनने के लिए प्रेरित करें।

भाजपा का तंज: नकली संविधान बचाने वाले राहुल गांधी गायब!

कहा- अब कांग्रेस को कौन बचाएगा?

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जैसे ही देश में चुनाव आते हैं... हार के बाद विदेश चले जाना, यही राहुल गांधी की असली पहचान है! भाजपा ने पोस्ट में लिखा कि देश की राजनीति में सवाल सिर्फ़ चुनाव जीतने या हारने का नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारियाँ निभाने का भी है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ़ चुनाव जीतने और हारने तक ही सीमित है; देश की जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, देश की जनता... सिर्फ़ भाषणों का ही नहीं, बल्कि व्यवहार का भी हिसाब रखती है। पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है: #राहुल_कहाँ_हैं?

बीजेपी ने एक और पोस्ट में लिखा कि Oh no! भारत के नकली संविधान बचाने वाले कहीं नहीं मिल रहे हैं! अब बेबस कांग्रेस को कौन बचाएगा? क्या हम कबूतरों के ज़रिए संदेश भेजें? दूध के कार्टन पर उनकी तस्वीर छापें? या फिर कोई नया रियलिटी शो शुरू करें: #WhereIsRahul? बीजेपी ने कई सार्वजनिक और संस्थागत मंचों पर गांधी की गैर-

मौजूदगी पर अक्सर सवाल उठाए हैं और इसे संसदीय कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और संवैधानिक परंपराओं का अनादर बताया है। पार्टी अक्सर उनकी लीडरशिप की आलोचना करने के लिए संसद में उनकी कम उपस्थिति, बार-बार विदेश यात्राओं और अहम राष्ट्रीय कार्यक्रमों से उनकी गैर-मौजूदगी का मुद्दा उठाती रही है।

उदाहरण के लिए, बीजेपी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल न होने पर गांधी की कड़ी आलोचना की, खासकर विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर। बीजेपी ने गांधी पर तब भी निशाना साधा जब वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह जैसे अहम संवैधानिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए; पार्टी ने उन पर संस्थागत सम्मान के बजाय राजनीतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला किया। उन्होंने प्रधान पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया और मांग की कि वे देश के युवाओं से माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफ़ा दें।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अहंकारी हो गई है और अब उन छात्रों को निशाना बना रही है जो अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और रोज़गार के मौकों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा, गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह से जुड़े एक कथित मानहानि वाले बयान पर खेद व्यक्त किया।

खेल
प्रमुख समाचार

जर्मनी को हराकर इतिहास रच गया इक्वाडोर

न्यू जर्सी। फीफा विश्व कप 2026 से एक बेहद चौंकाने वाली और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। ग्रुप-ई के अपने आखिरी मुकाबले में अंडरडॉग मानी जा रही इक्वाडोर की टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 से धूल चटा दी है। स्थानीय समयानुसार गुरुवार (25 जून) को न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में जीत दर्ज कर इक्वाडोर ने विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में जगह पक्की कर ली है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कर दी है।

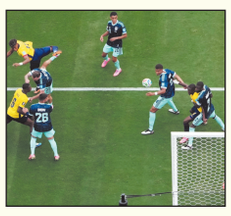

इक्वाडोर के लिए यह राह आसान नहीं थी। टीम को अपने पहले मैच में आइवरी कोस्ट से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि कुराकाओ के खिलाफ दूसरा मैच गोलरहित ड्रा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की टीम पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुकी थी और मैच में जीत की प्रबल दावेदार थी।

मैच की शुरुआत में जर्मनी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। फ्लोरियन विर्ट्ज़ के पास पर लेरॉय साने ने मैच का पहला शॉट सीधे गोल पोस्ट के भीतर दागकर जर्मनी को शुरुआती बढ़त दिला दी। साने ने बड़ी ही आसानी से गेंद को इक्वाडोर के गोलकीपर हर्नान गैलिंडेज को छकाते हुए निचले बाएं कोने में डाल दिया। इस गोल के तुरंत बाद इक्वाडोर के खिलाड़ियों ने फाउल की अपील की। रीप्ले में भी यह देखा गया कि गोल से ठीक पहले जर्मनी के अलेक्सांद्र पाव्लोविच का पैर इक्वाडोर के मिडफील्डर प्रेडो विटे के सिर पर लगा था, लेकिन अंपायर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। शुरुआती झटका लगने के बावजूद इक्वाडोर ने हिम्मत नहीं हारी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

भारत आने वाले तेल टैंकरों का किराया 9 गुना बढ़ा

नईदिल्ली। खाड़ी देशों में तनाव कुछ कम होने की खबर के बीच एक नई मुसीबत सामने आ रही है। युद्ध विराम के बाद अब होर्मुज से जहाजों का आना-जाना तो दोबारा तेजी से शुरू हो गया है लेकिन अब वहां जहाजों की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से भारत आने वाले एक बड़े तेल टैंकर का किराया सामान्य दर से करीब 9 गुना ज्यादा तय हुआ है जो इस साल का सबसे महंगा किराया बताया जा रहा है। इसके साथ दक्षिण कोरिया की शिपिंग कंपनी सिनोकोर की इस बुकिंग ने साफ कर दिया है कि होर्मुज वाला संकट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब एक नए रूप में सामने आ गया है। फारस की खाड़ी से भारत तक कच्चा तेल लाने के लिए जिस बड़े जहाज को बुक किया गया है, उसमें करीब 20 लाख बैरल तेल आ सकता है। शिप ब्रोकर्स के मुताबिक इसका किराया सामान्य से लगभग 9 गुना ज्यादा तय हुआ है।

सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सप्लाई से हटाईं सभी पाबंदियां

नईदिल्ली। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति में कुछ सुधार होने के बाद भारत सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर-वाइज पाबंदियां हटा ली हैं और कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है। इस फैसले से उन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को राहत मिली है जो अपने कामकाज के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और बल्क एलपीजी पर निर्भर हैं। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर लगी सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की और राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की बिक्री पर लगी पाबंदियों में ढील देने के बारे में सूचित किया।

सीएम फडणवीस ने 1,722 करोड़ की सड़क परियोजना को दी मंजूरी

मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर उप-समिति ने 1,722.40 करोड़ रुपये की एक नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह 3.55 किलोमीटर लंबी सड़क वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक के बांद्रा फोर्ट छोर को सावरकर सी ब्रिज से जोड़ेगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम इसका क्रियान्वयन करेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली उप-समिति ने गुरुवार को इसे हरी झंडी दी, जिसे 17 जून को मुख्य सचिव की समिति ने अनुमोदित किया था। इस सड़क से वर्ली से फोर्ट की यात्रा का समय 45 मिनट से घटकर 5-10 मिनट हो जाएगा। फोर्ट से वर्सोवा का समय भी एक घंटे से 15-20 मिनट रह जाएगा। परियोजना में 40 झुग्गियों का पुनर्वास भी शामिल है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का मुआवजा तय है। मछुआरों को 20 करोड़ रुपये और पर्यावरणीय उपायों के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट है।

कांग्रेस और शरद पवार से भी नाराज हैं उद्धव ठाकरे?

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की नाराजगी सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे से ही नहीं है बल्कि महाविकास अघाड़ी के अपने साथियों से भी है. उद्धव ने अपने 6 सांसदों की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के न पूरे विधायक पहुंचे और न ही बड़े नेता. महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बैठक उद्धव ठाकरे ने पूछा कि हम कहते तो हैं कि साथ हैं, लेकिन क्या हम वकायी में साथ हैं. महाविकास अघाड़ी की एकता सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि अगर गठबंधन सच में साथ है तो यह बात सड़क और सदन के भीतर भी दिखनी चाहिए. उद्धव ठाकर ने जिस तरह महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर संदेह जाहिर किया है।

फ्रीबीज कल्चर से बिगड़ रही है राज्यों के सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता

एम गोविंद राव

चुनावी फायदे के लिए केंद्र औ ?र राज्य स्तर पर लगातार बढ़ती सब्सिडी और अन्य हस्तांतरणों के चलते यह चिंता बढ़ी है कि हाल के पश्चिम एशियाई संकट जैसे बाहरी झटकों के समय सरकार अर्थव्यवस्था को बचाव मुहैया कराने में सक्षम रह पाएगी या नहीं। जंग के लंबा खिंचने के साथ ही ये कमजोरियां और अधिक स्पष्ट होती रहीं। ऐसा लगा कि सरकार उपभोक्ताओं को आपूर्ति की कमी, महंगाई, धीमी वृद्धि, विनिमय दर में गिरावट और चालू खाते के असंतुलन से बचाने में सक्षम नहीं हो सकती है।

ऊर्जा की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ और पश्चिम एशिया में संघर्ष लगातार जारी रहने के कारण वे ऊंची बनी रहीं। कच्चे तेल की कीमतों में हर10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से चालू खाते का घाटा अनुमानित रूप से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 0.4 फीसदी तक बढ़ जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को पहले के 6.9 फीसदी से घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है और महंगाई अनुमान को 4.6 फीसदी से बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के अलावा, वर्ष के लिए अनुमानित घाटा भी वृद्धि और महंगाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एक स्वस्थ राजकोषीय वातावरण में केंद्र और राज्य सरकारें प्रभावित और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए आवश्यक बचाव प्रदान कर सकती हैं। हालांकि ऐसा राहत देने के लिए अब बहुत कम राजकोषीय गुंजाइश है। मुफ्त उपहारों या रेवड़ी की संस्कृति केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों में गहराई तक पैठ बना चुकी है और सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही है।

एक बार अपनाने के बाद इसे त्यागना

कठिन हो जाता है और यह बीमारी सार्वभौमिक हो जाती है। हर चुनाव चक्र के साथ इसका परिमाण बढ़ता है और यह स्थिरता तथा वृद्धि पर बहुत भारी अवसर लागत थोपता है। लगभग दो-तिहाई सार्वजनिक खर्च राज्य स्तर पर होता है और उनके पास अतिरिक्त राजस्व तक पहुंच नहीं है, इसलिए बढ़ती निःशुल्क उपहार की संस्कृति बुनियादी ढांचे और मानव विकास पर होने वाले खर्च को सीमित कर देती है।

दुर्भाग्यवश विश्लेषक मुख्य रूप से घाटे और ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे राज्य खर्च की गुणवत्ता में गिरावट पर अ ?धिक ध्यान नहीं दिया गया है। समग्र स्तर पर देखें तो राज्यों के राजकोषीय घाटे और ऋण ने कोई गंभीर चेतावनी नहीं दी है।

जैसा कि 16वें वित्त आयोग ने कहा है, 'राज्य की समग्र वित्तीय तस्वीर कुछ चिंताएं पैदा करती है लेकिन यह चिंताजनक नहीं है। अधिक गंभीर कमजोरियां तब सामने आती हैं जब हम अलग-अलग राज्यों को देखते हैं।' (पृष्ठ 107, पैरा 5.81)।

रिजर्व बैंक के वार्षिक राज्य वित्त लेख में भी कहा गया है, 'ज्सकल राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात केंद्र द्वारा निर्धारित 3.5 फीसदी की सीमा (जिसमें 0.5 फीसदी बिजली क्षेत्र सुधार से जुड़ा है) के भीतर बना रहा। सतत उच्च पूंजीगत व्यय राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को मजबूत करता है और यह मध्यम अवधि की वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है।' (राज्य वित्त- बजट अध्ययन 2025-26, रिजर्व बैंक।)

हालांकि ये बातें राज्यों में उभर रही राजकोषीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न बीमारी को उजागर नहीं करतीं। घाटा और ऋण व्यापक रूप से नियंत्रित रहे क्योंकि राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उधार की मात्रा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। विशेषकर जब राज्य उसके ऋणी होते हैं। व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण मुख्यतः केंद्र का कार्य है इसलिए राज्यों के उधार पर नियंत्रण केंद्र सरकार को व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण को संतुलित करने में मदद करता है।

लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना और पूंजी निवेश के माध्यम से क्षमता निर्माण पर खर्च करना राज्यों की दीर्घकालिक वृद्धि बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसलिए उपहारों की बढ़ती संस्कृति को उनके खर्च की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में देखा जाना चाहिए।

हाउसिंग बोर्ड अब नए नाम और नए मिशन के साथ बनेगा विकास की रीढ़: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगो का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में आवास बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रा के माध्यम से कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सहित विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का नया लोगो तैयार करने वाले श्री अंशुल कश्यप को शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि ढाई लाख रुपए का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होने का सपना होता है और राज्य सरकार इस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केवल गृह निर्माण तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आर्थिक चुनौतियों से उबरते हुए मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडल के अध्यक्ष तथा पूरी टीम को बधाई दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों और वायदों को तेजी से पूरा किया है। सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद साढ़े दस लाख से अधिक परिवार के आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 नए आवास तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से 15 हजार अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए गए हैं तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी विशेष आवास योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'सेवा सेतु' के माध्यम से 450 से अधिक शासकीय सेवाएं अब मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 भी प्रारंभ की गई है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 65 हजार घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से सरकार घर में सोलर संयंत्र लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी भी दे रही है और इन परिवारों लिए आने वाले समय में बिजली पूरी तरह मुफ्त हो जाएगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच पाएंगें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से लंबित बिजली बिल के भुगतान का भी बड़ा अवसर दिया है और बिल पर लगने वाले सरचार्ज समेत आकर्षक छूट का प्रावधान किया है। श्री साय ने कहा कि सरकार न केवल जनहितैषी योजनाएं लागू कर रही है बल्कि सुशासन तिहार के माध्यम से उसका फीडबैक लेने लोगों के बीच भी गई।

बस्तर क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: कश्यप

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज मर्दापाल क्षेत्र के ग्राम मड़ागांव में लगभग 8 करोड़ 63 लाख 78 हजार रुपये की लागत से विभिन्न सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

भूमिपूजन के अंतर्गत खोड़सानार से नवागांव तक 2.30 किलोमीटर डामरीकरण सड़क निर्माण, बांसगांव-जोगियालवाड़ मार्ग पर फोटकी नाला में मध्यम पुल का निर्माण, मर्दापाल-बयानार मार्ग पर नवागांव से एहरा तक पुलिया एवं एप्रोच निर्माण, आदनार क्षेत्र में तीन पुलियों का निर्माण तथा तोड़म मेन रोड से मुंडापारा तक 2.65 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से बारिश के मौसम में आने-जाने की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा और गांवों की सड़क संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत होगी।

इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य विकास को गांव-गांव तक पहुंचाना है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, पुल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलती है, विद्यार्थियों को शिक्षा, मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन का लाभ मिलता है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की कमेटी यूसीसी पर लेगी सुझाव: साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर, अटल नगर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि, विष्णु देव साय सरकार छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विभिन्न वर्गों एवं समाज के लोगों से सुझाव आमंत्रित करेगी। इन सब बातों पर विचार कर अपना प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर सरकार उस पर विचार कर आगे बढ़ेगी।

श्री साव ने कहा कि, देश के विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो चुकी है और उसका पूरे राज्य में स्वागत हुआ है। यूसीसी के लिए देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार प्रदान किया

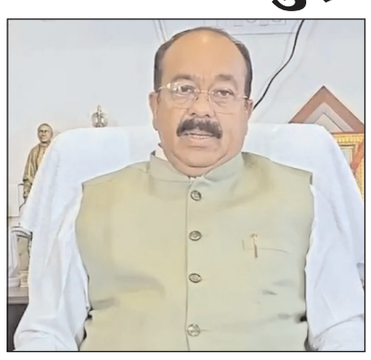

है। छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। सरकार रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्यवाही करेगी।

श्री साव ने कहा कि,कांग्रेस हर बात पर भ्रम फैलाने और झूठ बोलने का काम करती है। समान नागरिक संहिता पर अभी भी झूठ बोल रही है। बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।श्री साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेसियों की बार बार बुरी हार से बीपी बढ़ी हुई है। जबकि भाजपा लगातार जनाधार बढ़ने से उत्साहित होकर देश सेवा कर रही है। आज देश के 80 प्रतिशत भू भाग में भाजपा, एनडीए की सरकार है। इससे समझ सकते हैं बीपी किसका बढ़ा होगा। इनकी हालात क्या होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में विशेषज्ञ के रूप में एल्डरमैन की नियुक्ति का प्रावधान है। उस प्रावधान के अनुसार रायपुर और सरगुजा संभाग के सभी नगरीय निकाय में नियुक्ति की गई है। शेष संभाग में भी एल्डरमैन की नियुक्ति होगी। सोच विचार कर ही नियुक्ति की गई है।

मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ी

रायपुर। तकनीकी शिक्षा को सुशासन और नवाचार से जोड़ने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के अंतर्गत एम.टेक. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 कर दी गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित थी। यह कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT-NR में संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह ?50,000 की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही उनकी ट्यूशन फीस का संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों में वास्तविक परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतिभाशाली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा शासन की डिजिटल सेवाओं और नवाचार आधारित पहलों में योगदान देने का अवसर भी मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी, जिनका मूल निवास छत्तीसगढ़ का हो, 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए IIIT-NRकी वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण का अवलोकन किया जा सकता है।

28 जून को सीएम साय करेंगे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित

रायपुर। देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस माने जाने वाले 25 जून 1975 को लगाये गये आपातकाल की स्मृति को जीवित रखने तथा नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस तथा 26 जून को आपातकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है । लोकतंत्र प्रहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि 26 जून 1975 से मार्च 1977 तक चल 21 माह के आपातकाल को देश कभी मूल नहीं कर सकता उस कालखंड में नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया गया एवं हजारों लोकतंत्र समर्थकों को मीसा अन्य कठोर कानूनों के अत्तर्गत जेलों में बद किया गया तथा प्रस की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए गए। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया।

उपासने ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 28 जून को प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोजित भव्य सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा साथ ही इस अवसर पर आपातकाल मोड़ा सदर्भ ग्रंथ स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा।

विशेष आकर्षण यह होगा की लोकतंत्र सेनानी राघ व प्रहरी के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर प्रदेश स्तर की आपातकाल कभी विस्मृत न हो एवं 25 जून संविधान हत्या दिवस की प्रासंगिकता इन विषयों पर निका प्रतियोगिता आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा विजयी प्रथम द्वितीय तृतीय चयनित छात्रों को विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर 31000, 21000 व 11000 रुपए नगद पुरस्कार दोनों स्तरों पर गय स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। उसी प्रकार सनी 520 शामिल विद्यार्थियों सहित विद्यालय व महाविद्यालय के प्राचार्य को भी मुख्यमत्री द्वारा 28 जून को सम्मानित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

यूसीसी अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश: दीपक बैज

रायपुर। साय सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होता तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को होगा। यूसीसी छत्तीसगढ़ के आदिवासियां के खिलाफ है, राज्य में केवल आदिवासी ही ऐसे है जिन्हें प्रदेश में निवासरत अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष संवैधानिक

संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए विशेष नागरिक प्रावधान लागू है। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है, संरक्षित जनजातियां है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले है। उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून लागू है और 5 अनुसूची लागू है और भाजपा यूसीसी लाकर आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की कोशिश में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब से बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा हुई है उसके बाद से ही भाजपा के समर्थित उद्योगपति बस्तर में आदिवासियों की जमीन पर नजरे गड़ाये हुए है। बस्तर में भाजपा के समर्थित उद्योगपतियों की नजर लग चुकी है और वह आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते है। यूसीसी लाने की कवायद इसीलिए है।

प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने किया सियान गुड़ी का अवलोकन

रायपुर। जशपुर जिले के भागलपुर रोड स्थित डे-केयर सेंटर सियान गुड़ी का छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा से आए वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप संचालित यह केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, देखभाल और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल के रूप में विकसित हो रहा है। मैदानी प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ आत्मीय संवाद कर उनके जीवन अनुभवों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को करीब से समझा। इस दौरान उन्हें प्रशासनिक दायित्वों के साथ मानवीय संवेदनशीलता, जनसेवा और जरूरतमंद नागरिकों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर मिला।प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर रविशंकर वर्मा, निधि प्रधान, नंदनी साहू, मनीष बघेल, सौरभ दीवान,लखेश्वर यादव एवं सत्येन्द्र कुमार बंजारे ने केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन किया।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने चौपाल लगाकर किया संवाद

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने उत्तर बस्तर कांकेर प्रवास के दौरान अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम बोड़ागांव स्थित सीएएफ कैंप परिसर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी ढाई महीने के भीतर प्रत्येक ग्रामीण का बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंच सके। ग्रामीणों की टीम गठित कर गुजरात में एक्पोजर विजिट कराने के निर्देश अधिकारियों को उप मुख्यमंत्री शर्मा ने चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को आजीविका के साधन के रूप में विकसित करने तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आधुनिक ढंग से दुग्ध उत्पादन के लिए इसमें रुचि लेने वाले 10-10 ग्रामीणों की टीम गठित कर गुजरात में एक्पोजर विजिट कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना: 3 जुलाई तक करें आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। योजना के तहत श्रमिक परिवारों के बच्चों को देश एवं प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 03 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ उन श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलेगा, जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत एवं सक्रिय सदस्य हैं। चयनित विद्यार्थियों को सीबीएसई अथवा आईसीएसई पाठ्यक्रम संचालित प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिलेगा। योजना के तहत चयनित बच्चों की शिक्षा, आवास, भोजन, गणवेश, पुस्तकें एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री का संपूर्ण खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। पात्र श्रमिक विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल अथवा च्वाइस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही श्रम विभाग के कार्यालय से सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

मनरेगा कर्मचारी संघ का राज्यव्यापी आंदोलन 2 से

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगो को लेकर 2 जुलाई से राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया है जो जनपद पंचायत से शुरू होगा और राज्य स्तर

पर आकर राजधानी रायपुर में संपन्न होगा।जिसमें करीब 12 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आंदोलन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले चरण में 2 जुलाई को सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जायेगा। आंदोलन के दूसरे चरण में 3 जुलाई को जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और 4 जुलाई को राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन आयोजित किया जाएगा। मनरेगा कर्मचारी लंबे समय से ग्रेड पे लागू करने, एचआर पॉलिसी बनाने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और सेवा संबंधी अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार शासन के समक्ष मांगें रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ का दावा है कि इस आंदोलन में प्रदेशभर के 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारी हिस्सा लेंगे।

डिजिटल सेवाओं से मजबूत हो रहा सुशासन

सेवा सेतु बना ग्रामीणों का भरोसेमंद डिजिटल सहारा

रायपुर। जिला प्रशासन बीजापुर की डिजिटल पहल सेवा सेतु ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए सुशासन का प्रभावी माध्यम बन रही है। सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से अब नागरिकों को विभिन्न शासकीय प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल रही हैं। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं तथा शासन के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

विकासखंड भैरमगढ़ की ग्राम पंचायत तड़केल निवासी वंदना हेमला ने सेवा सेतु केन्द्र नेलेसनार के माध्यम से स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद उसी दिन उनका आवेदन निराकृत कर स्थानीय निवास

प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

सेवा सेतु केन्द्र के प्रबंधक श्री मुकेश कुमार बघेल ने उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किया। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध रही, जिससे उन्हें किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

समय और पैसे दोनों की हुई बचत

वंदना हेमला ने बताया कि पहले किसी भी शासकीय प्रमाण-पत्र के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों खर्च होते थे। लेकिन सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान रही और उन्हें एक ही दिन में प्रमाण-पत्र मिल गया। इससे उनके जरूरी कार्य भी समय पर पूरे हो सके।

ग्रामीणों के लिए वरदान

वंदना हेमला का कहना है कि सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से अब सरकारी सेवाएं गांव के नजदीक ही उपलब्ध हो रही हैं। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ से भी मुक्ति मिली है।

जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा संचालित सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय निवास, जाति, आय, जन्म, मृत्यु, विवाह सहित अनेक शासकीय सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल शासन की डिजिटल सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है।

हितग्राही की जुबानी

ग्राम तड़केल, विकासखंड भैरमगढ़ निवासी वंदना हेमला ने बताया कि सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से मुझे स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र बहुत कम समय में मिल गया। पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल एवं जिला प्रशासन बीजापुर और सेवा सेतु केन्द्र का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

बहुमंजिला भवनों के लिए फायर और लिफ्ट सुरक्षा नियमों पर सख्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) और लिफ्ट सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विस्तृत एडवाइजरी भेजी गई है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि बहुमंजिला आवासीय, वाणिज्यिक तथा मिश्रित उपयोग वाले भवनों में रहने वाले नागरिकों और आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए फायर सेफ्टी सिस्टम और लिफ्ट संचालन से जुड़े सभी मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय भवन संहिता एनबीसी-2016), भारतीय मानक ब्यूरो) के मानकों तथा छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य भवनों में आग से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है। निर्देशों के अनुसार सभी नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला भवनों की जांच सुनिश्चित करनी होगी। यह भी देखा जाएगा कि फायर सेफ्टी उपकरण जैसे अग्निशमन यंत्र, अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और आपात निकासी मार्ग पूरी तरह से मानकों के अनुरूप हों या नहीं। इसके साथ ही लिफ्ट संचालन की सुरक्षा व्यवस्था, नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी जांच को भी अनिवार्य किया गया है।

राज्य सरकार ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भवन प्रबंधन समितियों, हाउसिंग सोसायटियों, कॉलोनाइजरों और मेंटेनेंस एजेंसियों को इन नियमों की विस्तृत जानकारी दें।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.